लखनऊ

शुक्रवार 6 फरवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 167

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते मे किसी से पूछा नहीं कि समुंद्र कितनी दूर है।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

संक्षेप

विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप, जयराम रमेश बोले-राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया तो सदन नहीं चलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध पर संसद में अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई तो सदन के चलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि संसद में केवल एक ही मुद्दा है जो विपक्ष को परेशान कर रहा है, और वह यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने से रोका गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने भी यही मुद्दा उठाया। राज्यसभा में विपक्षी सांसद भी आज इसी मुद्दे पर सदन से बाहर चले गए। रमेश ने आगे कहा कि सभी विपक्षी दल इस बात पर एकमत हैं कि अगर लोकसभा सांसद को बोलने नहीं दिया गया, तो सदन के चलने की संभावना बहुत कम है। कांग्रेस ने संसद में कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा पूर्वी लद्दाख में 2020 के चीन गतिरोध पर एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा सांसद राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (सेवानिवृत्त) के उद्धरण देने से कई बार रोकार गया। भाजपा नेताओं ने बचाव में कहा कि यह सदन के नियमों का उल्लंघन है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल गिरने का खतरा है। संसद में लगातार हो रही बाधाओं के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग न लेने का फैसला किया। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि जून 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव में इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि उन्हें जवाब देने से रोका गया था। उन्होंने आगे कहा कि मनमोहन सिंह ने 2005 में राष्ट्रपति को दो बार धन्यवाद दिया था।

छत्तीसगढ़ में अमित शाह का एक्शन प्लान, मिशन 2026 के तहत नक्सलियों पर होगा फाइनल प्रहार!

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा के लिए 7 से 9 फरवरी तक दौरे पर रहेंगे। अमित शाह नक्सली स्थिति पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और रायपुर में अतिरिक्त बैठकें करेंगे। दौरे के दौरान वे बस्तर पांडुम कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार 31 मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के अपने संकल्प को और मजबूत कर रही है। इससे पहले दिन में, सुरक्षा बलों ने आज सुबह बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में एक मुठभेड़ में एक माओवादी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक एके-47 राइफल भी जब्त की। इसी बीच, सुकमा जिले के गोगुंडा गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने माओवादियों की केंद्रीय समिति के सदस्य रावुला श्रीनिवास उर्फ रामन्ना के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। यह घटना सीआरपीएफ द्वारा 20 नवंबर, 2025 को गोगुंडा में एक अग्रिम परिचालन बेस स्थापित करने के बाद घटी है, जिससे इस क्षेत्र में नक्सलियों के लंबे आतंक का अंत हुआ। एएनआई से बात करते हुए, 74वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट विदेखो किये ने कहा, 'गोगुंडा का यह क्षेत्र लंबे समय से नक्सलियों के नियंत्रण में था।

राहुल पर नड्डा की खरगे को सलाह, बोले- कांग्रेस को अबोध बालक का बंधन न बनाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के बजट सत्र का गुरुवार यानी आज सातवां दिन है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू की गई। हालांकि इसे तुरंत ही स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा की बात राज्यसभा मत करिए। कांग्रेस पार्टी को अहंकार से बचना चाहिए। पार्टी को अबोध बालक का बंधक न बनाएं।

कार्यवाही के दौरान ही संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे से कहा- 4 दिन हो चुके हैं। राहुल गांधी नियम नहीं मानते हैं। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं हैं। आपको समझना चाहिए।

संसद का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहा है। बुधवार को पीएम मोदी का लोकसभा में संशोधन होना था। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण उसे टाल दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आज यानी गुरुवार को पीएम मोदी राज्यसभा में अपना संबोधन दे सकते हैं।

लोकसभा में इस समय राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद पर चर्चा हो रही है। हालांकि शुरुआत के दो दिन राहुल गांधी के भाषण पर जमकर हंगामा हुआ। इसी कारण बुधवार को 8 सांसदों के निलंबित कर दिया गया।

उम्मीद है आज नियमों का होगा पालन- किरेन रिजिजू

राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज हम सभी उम्मीद करते हैं कि सभी सांसद सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करेंगे। सभी सांसद आज पीएम का भाषण सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पीएम का भाषण नहीं सुनना चाहती, तो भी बाकी सभी सदस्य सुनना चाहते हैं। आपके लोकसभा में विपक्ष के नेता सदन के नियमों का पालन नहीं करते।"

संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों- खरगे

राज्यसभा में बोलते हुए LoP मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में LoP देश के हितों पर बोलना चाहते थे। लेकिन ,उन्हें बोलने नहीं दिया गया। आप इस तरह से सदन कैसे चला सकते हैं?" केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, "LoP को पता होना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती है।

अबोध बालक को समझाओ- नड्डा

राज्यसभा में आज की कार्यवाही हंगामे से ही शुरू हुई। इस दौरान सदन में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। आप खुद ही स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी को चलाइए। सदन को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार बैठे थे, लेकिन आप लोगों ने सदन चलने ही नहीं दिया है। वे हर सवाल का जवाब देते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अहंकार से बचना चाहिए।

एनसीआर में मौसम में बदलाव के संकेत, तापमान में बढ़ोतरी के साथ वायु गुणवत्ता फिर खराब श्रेणी में

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक बार फिर मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलता नजर आ रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड के असर में कमी आने लगी है और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान बढ़ने के साथ-साथ वायु प्रदूषण ने भी चिंता बढ़ा दी है। एनसीआर के अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार 5 फरवरी से 10 फरवरी तक एनसीआर में मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। 5 फरवरी को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। 6 और 7 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास रहेगा, वहीं 8, 9 और 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को दिया जीत का मंत्र, 'देश को गौरवान्वित करेंगे'

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को साउथ ब्लॉक से अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6,961 मीटर ऊँचा यह पर्वत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी और एशिया के बाहर सबसे ऊँचा पर्वत है। यह संयुक्त अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस), पहलगाम द्वारा संचालित किया जा रहा है।

रक्षा मंत्री ने एनआईएम और जेआईएम एंड डब्ल्यूएस को साहस, दृढ़ता और संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए कर्मियों को तैयार करने के लिए बधाई दी। टीम को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि इस दुर्गम चोटी पर चढ़ाई करना केवल शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि नेतृत्व, टीम वर्क और मानसिक दृढ़ता की सच्ची परीक्षा है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों की पहचान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीम के सदस्य दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी और एशिया के बाहर सबसे ऊँचे पर्वत पर सफलतापूर्वक अभियान पूरा करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। रक्षा मंत्री ने टीम को शुभकामनाएं दीं और पर्वतारोहण अभियान में उनकी सफलता पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माउंट एकोनकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अद्भुत है। आप सभी ने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

भाजपा सांसद ने कांग्रेस और गांधी परिवार का इतिहास बताने वाली 40 किताबों की लिस्ट जारी की

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर संसद में चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर पलटवार किया है। उन्होंने 40 किताबों की एक लिस्ट शेयर की, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे भारत का असली इतिहास बताती हैं और पार्टी के पिछले शासन से जुड़े कथित विवादों को उजागर करती हैं। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 40 किताबों की एक लिस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि इन किताबों में भारत के ऐतिहासिक वृत्तांत, 1975 और 1977 के बीच आपातकाल की अवधि, वंशवादी राजनीति की आलोचना और अन्य विवरण शामिल हैं। किताबों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि वे कांग्रेस शासन के विवादास्पद पहलुओं को उजागर करती हैं। भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 40 अलग-अलग पोस्ट किए, जिनमें से हर एक में उनकी लिस्ट की एक किताब का शीर्षक, लेखक और सारांश शामिल था। निशिकांत दुबे ने तर्क दिया कि अप्रमाणित सामग्री पर चर्चा करने के बजाय संसद को उन किताबों पर विचार करना चाहिए, जो पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। निशिकांत दुबे के अनुसार, ये किताबें नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस सरकारों के असली इतिहास पर प्रकाश डालती हैं।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्दीकी पर विश्वविद्यालय के संचालन में जालसाजी और भारी अनियमितताएं बरतने का आरोप है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी कि यह गिरफ्तारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ट्रस्ट) की ओर से दर्ज कराई गई दो एफआईआर के आधार पर की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले की कड़ियाँ लाल किले के पास हुए धमाके के बाद शुरू हुई जांच से जुड़ती हैं। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच का दायरा बढ़ाया, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई तरह के फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के संकेत मिले। जांच के दौरान मिले ठोस तथ्यों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू की थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) भी पहले से सक्रिय था और अपनी ओर से कार्यवाही कर रहा था। ईडी की जांच और मिले सबूतों के बाद दिल्ली पुलिस ने सिद्दीकी को हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जावेद अहमद सिद्दीकी को कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत के सामने दलील दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से गहन पूछताछ की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए सिद्दीकी को चार दिन की पुलिस हिरासत (रिमांड) में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिमांड के दौरान यूनिवर्सिटी के अन्य वित्तीय लेन-देन और कथित फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम विवादों में आना नया नहीं है।

'चांद और सूरज छोड़कर..': चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ पीआईएल, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच मार्च में सुनेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की ओर से 'तर्कहीन चुनावी रेवड़ियों' का वादा किए जाने के खिलाफ दायर की जनहित याचिका पर मार्च में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में ऐसे वादे करने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने या चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में यह मामला उठाया गया, जिसने इसपर मार्च में सुनवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। गुरुवार को इस मामले में याचिककर्चा और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि उनकी जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को 2022 में ही नोटिस जारी किया गया था और अदालत से गुहार लगाई कि इस मामले को सुनवाई के लिए जल्द लिस्ट किया जाए।

पागल कुत्ते का खौफ, 2 घंटे में 11 लोगों को काटा, मासूम बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोचा

आर्यावर्त क्रांति

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आवारा कुत्तों के आतंक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हैदरगढ़ क्षेत्र में बुधवार को एक पागल कुत्ते ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। महज दो घंटे के भीतर इस कुत्ते ने राह चलते 11 लोगों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना लिया। वहीं, कोठी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

हैदरगढ़ कस्बे में बुधवार शाम करीब चार बजे एक पागल कुत्ता घुस आया और जो भी उसके रास्ते में आया, उस पर झपट पड़ा। आतंक का यह सिलसिला हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से शुरू हुआ, जहां मालिनपुर से बाइक पर आ रहे 22 वर्षीय अंकुश के पैर में कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद कुत्ते ने सड़क पार कर रहे लिल्हौरा वार्ड के कुंदन कुमार और विमला देवी को अपना निशाना बनाया। मुख्य चौराहे के पास पान की दुकान पर जा रहे दयाशंकर मिश्र पर भी कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उनका पैर मुंह में भर लिया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह कुत्ते को खदेड़कर उनकी जान बचाई। रायबरेली मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कुत्ते ने मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग हनीफ समेत मोहम्मद दाऊद, अनवर, निसार अहमद और 9 साल की बच्ची अल फिजा को भी काट खाया। शाम चार बजे से छह बजे तक पागल कुत्ते ने पूरे कस्बे में दहशत का माहौल बना दिया। लगातार हो रहे हमलों से घबराए स्थानीय लोग लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर निकल आए। भीड़ को अपनी तरफ आता देख कुत्ता पास के जंगल की ओर भाग निकला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और नगर पंचायत अध्यक्ष को सूचना देकर मांग की है कि जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया जाए।

'कांग्रेस के कई सदस्य अप्रिय घटना कर सकते थे, पीएम से सदन में न आने का आग्रह किया', लोकसभा स्पीकर का बड़ा बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि कल सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन के नेता के आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए। बिरला ने यह भी कहा कि बुधवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनके चैंबर में आकर जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ और यह दृश्य एक 'काले धब्बे' की तरह था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा, इस सदन में बुधवार को कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, कि आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को आज तक सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया है।

कांग्रेस के सदस्य कर सकते थे अप्रत्याशित घटना: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यालय में जो व्यवहार किया। वह हमारी संसदीय परंपराओं के लिए अनुचित था। वह पल एक काले धब्बे की तरह था। हम सबको सदन सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, कि पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अधिभाषण का जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर यह घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय है। यह देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इस घटना को टालने के लिए मैंने पीएम मोदी से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा, ''कल की घटना देश ने देखी है कि किस तरह महिला सदस्य वहां (प्रधानमंत्री के बैठने के स्थान) तक पहुंची हैं। यह किसी तरह उचित नहीं था। सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। आप सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप शब्दों से बात कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप इधर (सत्तापक्ष की तरफ) आकर जिस तरह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।''

सीएम रेखा गुप्ता ने सुनीं दिल्लीवालों की समस्याएं, मौके पर ही दिए समाधान के निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित जनसुनवाई के दौरान शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से आए दिल्लीवासियों की समस्याएं और सुझाव ध्यान से सुने। 'जनता का शासन, जनता के द्वारा' के अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने न सिर्फ हर शिकायत को गंभीरता से लिया, बल्कि मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए।

जनसुनवाई में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, टूटी सड़कों, जलभराव और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। मुख्यमंत्री ने हर नागरिक से व्यक्तिगत बातचीत की और उनके प्रार्थना पत्रों पर तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसुनवाई में उठने वाली शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनसुनवाई केवल समस्याएं सुनने का मंच नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे को मजबूत करने का माध्यम है। जब कोई नागरिक सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखता है और उस पर कार्रवाई होती है तो प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है। हमारी सरकार पूरी तरह जवाबदेह है और दिल्ली के हर नागरिक की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। जनसुनवाई के दौरान दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आई महिलाओं और मध्यमवर्गीय परिवारों ने होली और दिवाली पर निशुल्क गैस सिलेंडर की राशि देने की योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

कांग्रेस ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अनियमितता का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पार्टी ने अपनी मांगों पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता, जिनमें उनके बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी शामिल हैं, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा किए जा रहे हैं।पार्टी ने आशंका व्यक्त की है कि बड़ी संख्या

में फॉर्म 7 जमा होने से इन समुदायों के मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। कांग्रेस के बीएलए द्वारा फॉर्म 7 में उल्लिखित नामों की सूची मांगने पर बीएलओ द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है।कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांग की है कि प्रत्येक बूथ पर भरे गए फॉर्म 7 में उल्लिखित नामों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही, फॉर्म 7 आवेदनकर्ताओं की पहचान सार्वजनिक करने और बीएलओ पर दबाव डालने वाले राजनीतिक सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। पार्टी ने यह भी मांग की है कि मतदाता सूची बनाने में गड़बड़ी के दोषी पाए जाने वाले बीएलओ को पद से हटाने का आदेश जारी किया जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। इस विरोध प्रदर्शन में वरुण मिश्रा, मोहित तिवारी, शरद श्रीवास्तव, हामिद राइनी, रणजीत सलूजा, पवन मिश्रा और मनीष तिवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

माफियाओं का आतंक, आश्रम के कांटे हरे पेड़ और उठा ले गए सारा सामान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता हुआ एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ खुलेआम गाली-गलौज, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी गई।हर जगह घटना की चर्चा हो रही है।

पी ड़ि त दयानन्द शाह, दाता,पुत्र स्व अ न मो ल शा ह , दा ता निवासी कोतवाली नगर कस्बा पाचोपीरन सत्य साईं दाता आश्रम सुल्तानपुर ने थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि नगर क्षेत्र में वर्षों से संचालित आश्रम के हरे वृक्षों को काटकर कई लोग उठा ले गए हैं। उन्होंने बताया कि वे भंडारे में गए हुए थे,जब भंडारे से 2 फरवरी को लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि बीस,बाइस पेड़ कटे हुए थे ।कटे हुए वृक्षों की आयु बीस साल से अधिक और सौ वर्ष तक थी। मंगलवार 3 फ़रवरी को आश्रम के दाता द्वारा शिकायती पत्र थाना प्रभारी और वन विभाग को दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि देखरेख करने वाले आश्रम की सच्चिदानंद साव की मिली भगत से ननकू सिंह, अजय,मनु सिंह, पुत्तन ,पटन ,मनीराम,मुंदरलाल, राजेंद्र यादव सहित दर्जनों लोगों द्वारा षड्यंत्र करके आश्रम के वृक्ष काटे गए।वे लोग आश्रम का सामान भी ताला तोड़कर उठा ले गए हैं।112 पर पीढ़ी द्वारा शिकायत की गई। सिपाही द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया गया परंतु खबर लिखे जाने तक कोई भी लिखित कार्यवाही नहीं की गई ।थाना प्रभारी से इस संदर्भ में बात हुई तो उन्होंने कहा प्रकरण संज्ञान में है। दोषी बक्से नहीं जाएंगे, दोषियों के विरुद्ध विधि कार्रवाई की जाएगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का महमूद मदनी ने किया स्वागत, निजी स्थान पर इबादत करने का मामला

आर्यावर्त संवाददाता

देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया कि निजी स्थान पर धार्मिक प्रार्थना या इबादत के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

महमूद मदनी ने बुधवार को कहा कि 27 जनवरी को आया हाई कोर्ट का यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक आजादी की पुष्टि करता है। कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों खासतौर पर यूपी में नमाज या अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर एफआइआर और गिरफ्तारियां की गईं, जो गलत थीं। हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसी सभी कार्रवाइयों के खिलाफ एक कठोर संवैधानिक चेतावनी है। मदनी ने कहा कि संविधान नागरिकों को अपने धर्म के आधार पर इबादत या पूजा-पाठ करने का अधिकार देता है, जिसे राज्य अपनी मर्जी से नहीं छीन सकते और न हो रोक सकते हैं। मदनी ने कहा कि पवित्र रमजान माह आने को है और इस महीने में विशेष तरावीह और अन्य इबादत की जाती हैं। उम्मीद है कि अदालत के इस निर्णय के बाद यूपी पुलिस इस तरह की गैर संवैधानिक कार्रवाई से बचेगी और लोगों की इबादत में रुकावट नहीं डालेगी।

अमन के लिए की दुआ

देवबंदः शब ए बराअत के मौके पर मदरसा जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह में हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ मुकम्मल कराई गई। इस दौरान फारिग (शिक्षा पूर्ण) होने वाले छात्रों की दस्तारबंदी हुई। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर देश व दुनिया में अमन के लिए दुआ हुई। वहीं, मुस्लिम समाज ने शब ए बराअत के मौके पर रात भर जागकर अल्लाह की इबादत की। मंगलवार की रात हुए कार्यक्रम में मदरसे के मोहतमिम मौलाना सैयद अहमद खिजर शाह मसूदी ने छात्रों को बुखारी शरीफ का अंतिम पाठ पढ़ाया और छात्रों से हासिल की गई तालीम की रोशनी को कोने कोने में फैलाने का आह्वान किया।

अंतर्जनपदीय 37वीं घुड़दौड़ प्रतियोगिता का हुआ भव्य आयोजन

कुड़वार/सुलतानपुर। क्षेत्र के गंजेहड़ी गांव में गुरुवार को अंतर्जनपदीय 37वीं घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता बीते 37 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है, जो ग्रामीण खेल परंपरा और आपसी भाईचारे की मिसाल बन चुकी है। प्रतियोगिता का आयोजन गांव निवासी अफसर खान के नेतृत्व में गंजेहड़ी ग्राउंड पर किया गया, जिसमें आसपास के कई जिलों से पहुंचे घुड़सवारों ने अपनी प्रतिभा और घोड़ों की रफ्तार का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों की दौड़ कराई गई। चौटाला दौड़ में अनिल (प्रतापगढ़) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अनवर सभासद द्वितीय और छत्री (प्रतापगढ़) तृतीय स्थान पर रहे। सिंधी दौड़ में अनवर (लखनऊ) ने बाजी मारी, वहीं अबरार फौजी (पलहीपुर) ने द्वितीय और अदनान (मंगरौरा) ने तृतीय स्थान हासिल किया।

मुरादाबाद में सोना–चांदी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 33 करोड़ की ज्वेलरी सीज

सोना चांदी के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से टैक्स चोरी का मामला गहरा गया था। इसको लेकर कई सराफा करोबारियों पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही थी। इसी में करीब 33 करोड रुपए की ज्वेलरी सीज की गई है।

- अशोक कुमार सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्यकर

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। सोना और चांदी के बाजार भाव में अप्रत्याशित वृद्धि के बीच टैक्स चोरी की आशंका को लेकर राज्य कर विभाग मुरादाबाद ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग को इनपुट प्राप्त हो रहे थे कि कुछ व्यापारी टैक्स चोरी के उद्देश्य से भारी मात्रा में सोना और चांदी की खरीद कर रहे हैं।

इसके तहत संभल के एक ज्वैलर को चिन्हित किया गया, जो कथित रूप से बड़े पैमाने पर बिना दस्तावेजों के सोना-चांदी की खरीद कर रहा था। लगभग एक माह तक उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए सूत्र लगाए गए। सूचना के आधार पर चार फरवरी 2026 को राज्य कर मुरादाबाद की प्रवर्तन विंग की 10 सदस्यीय टीम को संभल रवाना किया गया, जिसमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं।

जांच टीम ने पहले से चिन्हित ज्वैलर के शोरूम और आवास पर एक साथ दोपहर करीब एक बजे तलाशी की कार्यवाही शुरू की, जो लगातार 21 घंटे तक चली। पूरी तलाशी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्रवाई कैमरे की निगरानी में कराई गई। जांच के दौरान ज्वैलर शोरूम में मौजूद माल की खरीद से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।

ज्वैलर द्वारा जांच के समय स्टाक में केवल 439 ग्राम सोने की ज्वैलरी और 120 किलोग्राम चांदी की ज्वैलरी का ही हिसाब दिखाया गया, जबकि मौके पर 16,638 ग्राम सोने की ज्वैलरी, 875 किलोग्राम चांदी की ज्वैलरी और 34.43 कैरेट हीरा बरामद हुआ, जो स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं था। लेखा-पुस्तकों से बाहर मंगाई गई इस ज्वैलरी का बाजार मूल्य लगभग 33 करोड़ रुपये आंका गया। नियमानुसार पूरी ज्वैलरी को सीज कर दिया गया, जिसके बाद ज्वैलर द्वारा मौके पर ही 1.20 करोड़ रुपये कर एवं अर्थदंड के रूप में ऑनलाइन जमा कराए गए। तलाशी के दौरान शोरूम और आवास से कई लूज पर्चे तथा मोबाइल फोन में संग्रहित कारोबारी डाटा भी सीज किया गया है, जिसकी विस्तृत जांच की जाएगी। इस कार्रवाई में उपायुक्त बामदेव त्रिपाठी, उपायुक्त उत्तम तिवारी, सहायक आयुक्त रणंजय यादव, अखिलेश कुमार, पूजा दीक्षित, राहत चांद, राज्य कर अधिकारी रूपम उपाध्याय, अरविंद कुमार, धीरज सिंह और बिजेंद्र सिंह शामिल रहे। अपरायुक्त ग्रेट 2 एसआइबी आरए सेठ ने बताया कि 21 घंटे तक करवाई की गई गई।

'पहले आओ–पहले पाओ'... मेरठ आवास विकास परिषद ने फ्लैट रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई डेट, कीमत 8 लाख से शुरू

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के लोगों के लिए अपना घर खरीदने का सुनहरा मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देश पर मेरठ आवास विकास परिषद ने फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को अब 31 मार्च 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। वह अब नई लास्ट डेट तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। फ्लैट की कीमत 8 लाख रुपए से शुरू है।

योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा परिवारों को अपने आशियाने का सपना पूरा करने का अवसर देना है। मेरठ आवास विकास के अधिकारियों ने बताया कि जागृति विहार एक्सटेंशन में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इच्छुक आवेदक विभाग

की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

बुकिंग के समय कितना देना होगा पैसा?

बुकिंग के समय फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा, जो बाद में मूल राशि में जोड़ दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एफ-32, एफ-57 और एफ-64 श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध हैं, जो निर्माण गुणवत्ता और सुविधाओं के लिहाज से बेहतर माने जा रहे हैं।

एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगी छूट

योजना की खास बात यह है कि एकमुश्त भुगतान करने पर आकर्षक छूट दी जा रही है। यदि उपभोक्ता बुकिंग के बाद 60 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करता है, तो 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं 90 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा। हालांकि किस्तों में फ्लैट लेने वाले आवेदकों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों को कितनी छूट?

आवास विकास परिषद ने फ्लैट देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जो लोग खरीद से पहले मौके पर जाकर फ्लैट देखना चाहते हैं। वह जागृति विहार एक्सटेंशन पहुंचकर फ्लैट देख सकते हैं। इसके अलावा किस्तों पर खरीद की सुविधा भी दी गई है। सामान्य आवेदक 50 प्रतिशत राशि जमा कर कब्जा लें सकते हैं और शेष रकम किस्तों में चुका सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को विशेष सहूलियत देते हुए 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही कब्जा देने का प्रावधान किया गया है। शेष राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से किस्तें लागू होंगी।

कितनी है फ्लैट की कीमत?

फ्लैटों की कीमत 8 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक तय की गई है। एफ-32 फ्लैट की कीमत 8 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि एफ-57 की कीमत करीब 19 लाख रुपये और एफ-64 की कीमत 21 लाख रुपये निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक आवास विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं।

धोपाप धाम के विकास को 2 करोड़ मंजूर, पर्यटन मंत्री से मुलाकात के बाद आज से शुरू हुआ सर्वे

आर्यावर्त संवाददाता

लम्भुआ/सुल्तानपुर। जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल धोपाप धाम के समग्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री और धोपाप उन्नयन सेवा समिति के अध्यक्ष रवीन्द्र त्रिपाठी की पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया। विकास कार्यों के लिए स्थल का भौतिक सर्वे आज से शुरू हो गया है। यह तीर्थ स्थल सुलतानपुर की लम्भुआ तहसील में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम ने लंका विजय के उपरांत इसी स्थान पर स्नान और दीपदान किया था। प्रतिवर्ष जेठ दशहरा के अवसर पर यहां लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजन के लिए आते हैं। रवीन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि इस तीर्थ स्थल को अब पर्यटन विभाग की विकास सूची में शामिल कर लिया गया है। सीएडडीएस विभाग के अवर अभियंता अजय सिंह के नेतृत्व में एक तकनीकी

टीम ने व्यापारी नेता रवीन्द्र त्रिपाठी के साथ धोपाप धाम पहुंचकर स्थल का भौतिक सर्वे किया। प्रस्तावित कार्यों में पक्के स्नान घाटों का निर्माण, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार तथा अतिथि गृह का निर्माण शामिल है। इन सभी कार्यों के लिए विस्तृत सर्वे कर अनुमानित लागत (एस्टीमेट) तैयार किया गया है। रवीन्द्र त्रिपाठी के प्रयासों से ही यह धनराशि शासन से स्वीकृत हुई है। त्रिपाठी ने कहा कि धोपाप धाम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी राम अच्छेबर उपाध्याय, धीरज उपाध्याय, रणजीत शुक्ल, उमेश शुक्ला, रवि प्रकाश उपाध्याय सहित अन्य स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में पर्यटन मंत्री विनोद सिंह के कार्यकाल में धोपाप में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ था। रवीन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि वह लम्भुआ विधानसभा सहित पूरे सुलतानपुर जनपद के विकास के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में अन्य पौराणिक स्थलों के विकास के लिए भी लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

फाइलेरिया उन्मूलन को सफल बनाने के लिए मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित

"हमारा संकल्प – फाइलेरिया से मुक्ति", भ्रांतियाँ दूर कर एमडीए अभियान में 90% दवा सेवन लक्ष्य पर जोर

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान (एमडीए) से पूर्व गुरुवार को एक स्थानीय होटल में मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य मीडिया को अभियान की रणनीति, तैयारियों और प्रमुख संदेशों से अवगत कराते हुए जनसमुदाय में सही जानकारी का प्रसार करना था, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा सेवन से वंचित न रहे।

कार्यशाला के शुभारम्भ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डीके श्रीवास्तव ने किया। WHO के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉ. नित्यानंद ने बताया कि प्रदेश के 21 जनपदों सहित बाराबंकी में यह अभियान 10 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। बाराबंकी के सात ब्लॉक में अभियान चलाया जाएगा जिसमें कुल 1695911 जनसँख्या को कवर किया

जाना है । इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों की 1357 टीमें घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को अपने सामने फ़ाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएँगी। साथ ही 226 सुपरवाइज़र भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर एवं विकलांगता उत्पन्न करने वाला मच्छर-जनित रोग है, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण कई बार संक्रमण के 10–15 वर्षों बाद प्रकट होते हैं, इसलिए लोग अनजाने में इसके वाहक बने रहते हैं और संक्रमण फैलाते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डीके श्रीवास्तव ने जोर देते हुए कहा, "फाइलेरिया उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 90 प्रतिशत पात्र आबादी दवा का सेवन करे। इसलिए यह अभियान केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा जन-आंदोलन है।" सीएमओ ने कहा – "उत्तर प्रदेश सरकार फाइलेरिया उन्मूलन को गति देने के लिए पाँच-स्तम्भीय रणनीति (Five-Pillar Strategy) पर कार्य कर रही है। इसमें पहला स्तम्भ सर्वजन दवा सेवन अभियान है, जिसके माध्यम से 90% से अधिक कवरेज सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरा स्तम्भ रुग्णता प्रबंधन एवं रोकथाम (MMDP) है, जिसमें हाइड्रोसील सर्जरी, हाथीपांव मरीजों को किट वितरण तथा मामलों की IHIP पर सूचीबद्धता शामिल है। तीसरा स्तम्भ वाहक नियंत्रण है, जिसके अंतर्गत मच्छरों की रोकथाम, स्वच्छता एवं जल प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। चौथा स्तम्भ उच्च-स्तरीय एडवोकेसी एवं अंतर-विभागीय समन्वय है, जिसमें पंचायती राज, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की भागीदारी से अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। पाँचवाँ स्तम्भ नवाचारी दृष्टिकोण है, जिसमें डिजिटल टूल्स के माध्यम से रियल-टाइम रिपोर्टिंग और नए जांच उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। " हमारा संकल्प – फाइलेरिया से मुक्ति" के तहत अब हमें अभियान में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करनी है।" जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. राजीव सिंह ने कहा कि पेरीअर्बन एरिया में माइग्रेशन जैसी चुनौतियाँ अधिक हैं जिनकी वजह से इन सात ब्लॉकों में ख़ास तौर पर उन्मूलन गतिविधियों को तेज़ किया गया है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे यह संदेश जन-जन तक पहुँचाएँ कि दवा खाली पेट न लें, स्वास्थ्यकर्मी के सामने दवा अवश्य खाएँ, हल्के लक्षण शुभ संकेत हैं और आज दवा खाने से आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होंगी।

फाइलेरिया गंभीर रोग, लेकिन इसपर पूरी तरह रोक संभव

जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुजाता ने कहा कि अभियान की सबसे बड़ी चुनौती लोगों की झिझक, भ्रांतियाँ और दवा के बाद होने वाली हल्की प्रतिक्रियाओं (ADR) को लेकर डर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दवाएँ WHO प्रमाणित और पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कभी-कभी मतली, थकान जैसे हल्के लक्षण कुछ घंटों में स्वतः ठीक हो जाते हैं। गंभीर स्थिति के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम उपलब्ध रहेगी। सबके निरंतर प्रयास से 16 में से 9 ब्लॉक में हमने फ़ाइलेरिया पर काबू पा लिया है । इस बार हमें जागरूकता का स्तर इतना बढ़ाना होगा कि लोग खुद फाइलेरिया की जांच और उससे बचाव की दवा लेने स्वास्थ्य केंद्र तक आएं। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, सहयोगी संस्था पाथ, पीसीआई एवं सें सीफार के प्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पीएसपी सदस्यों ने साझा किये अनुभव

आयुष्मान आरोग्य मंदिर टीपहार के अंतर्गत सामुदायिक स्वस्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में बने रोगी हितधारक मंच (PSP) के सदस्य 28 वर्षीय फाइलेरिया रोगी कारण ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा - मैं पिछले पांच वर्षों से फाइलेरिया से पीड़ित हूँ। फाइलेरिया सिर्फ बीमारी नहीं, जिंदगी भर की परेशानी बन जाती है। मैं नही चाहता कि मेरी जैसी हालत किसी और की हो। इसलिए आप सभी से अपील है कि स्वास्थ्यकर्मी के सामने दवा ज़रूर खाएं। टीपहार के ग्राम प्रधान विजय कुमार ने बताया कि वे भी अब पीएसपी के साथ जुड़कर फ़ाइलेरिया मुक्त अभियान की अगुआई कर रहे हैं। पिछले एमडीए अभियन में उन्होंने स्वयं अपने घर से सामूहिक दवा खाकर अभियान का शुभारम्भ किया जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ गये।

केंद्र व राज्य स्तर के अधिकारियों ने भी लिया तैयारियों का जायज़ा

वर्ष 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को देखते हुए एमडीए अभियान सरकार की प्राथमिकता पर है । इसी को लेकर बुधवार को केंद्र की दो सदस्यी टीम ने बाराबंकी पहुंचकर अभियान की तैयारियों का जायजा लिया।

इन सात ब्लॉकों में चलेगा अभियान

डीएमओ ने बताया – देवा, दरियाबाद, रामनगर, हरख, सिद्धौर, जटाबरौली व बाराबंकी अर्बन में फ़ाइलेरिया की दर एक प्रतिशत से अधिक है जिस कारण यहाँ एमडीए अभियान चलाया जाएगा ।

जिले में फाइलेरिया की स्थिति

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में बाराबंकी जिले के 7 ब्लॉक फाइलेरिया की चपेट में हैं। जिले में फाइलेरिया के कुल 3617 मरीज़ हैं, जिनमें हाथीपाँव के 3188 और हाइड्रोसील के 429 मरीज़ शामिल हैं। सीएमओ ऑफिस स्थित फाइलेरिया क्लीनिक पर हर बुधवार को रात आठ बजे से फाइलेरिया की जांच की जाती है ।

राज्य ऋण संगोष्ठी 2026-27 में सीएम योगी का बड़ा बयान: अनलिमिटेड पोटेंशियल तभी दिखेगा जब विकसित भारत के साथ विकसित यूपी बनेगा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2026-27 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश है। यह क्षमता तब पूरी तरह सामने आएगी, जब विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियां प्रदेश की संभावनाओं को दिशा देने और आर्थिक सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभाती हैं।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा तैयार राज्य फोकस पेपर 2026-27 का विमोचन किया और ई-केसीसी पोर्टल का लोकार्पण भी किया। साथ ही एफपीओ, जिला सहकारी बैंक, महिला स्वयं सहायता समूह, पैक्स के कम्प्यूटरीकरण और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी में प्रगतिशील किसानों, एफपीओ, एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने वाले लोगों की सक्सेस स्टोरी प्रस्तुत की गई है, जिससे अन्य लोग भी प्रेरणा लेकर अपने करियर और कार्यक्षेत्र को साझा करने के लिए मंच मिलना चाहिए। इस मिल्क प्रोड्यूसर में 1005 सदस्य जुड़े हैं और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। इसी तरह मथुरा की 750 महिला सदस्यों वाली माँट मस्टर्ड उत्पादक कंपनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं मस्टर्ड ऑयल प्रोसेसिंग से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, जिसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आजादी के बाद पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और एफपीओ तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को हर स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। यूनियन बजट में शी-मार्ट की व्यवस्था कर ग्रामीण उत्पादों को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। न विकास था और न ही रोजगार के अवसर। सहकारी बैंकों पर माफिया हावी थे और 16 जिला सहकारी बैंक डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए थे। आज इनमें से 15 बैंक लाभ में हैं और शेष को भी मुनाफे की स्थिति में लाने का प्रयास जारी है। सहकारिता आज फिर से एक नए आंदोलन के रूप में उभर चुकी है।मुख्यमंत्री ने 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना को सरकार की साफ नीयत और मजबूत नीति का परिणाम बताते हुए कहा कि इस योजना से एमएसएमई सेक्टर को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है। प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां एमएसएमई इकाइयों को 5 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर दिया जा रहा है। आज प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जिन पर लगभग 3 करोड़ परिवारों की आजीविका निर्भर है। निर्यात 84 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और ओडीओपी योजना देश ही नहीं, दुनिया में उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है।मुख्यमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश का क्रेडिट-डेबिट रेशियो 43 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो चुका है और इसे मार्च तक 62 प्रतिशत तथा वर्ष 2026-27 में 65 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बैंकर्स से अपील की कि वे शर्तों को सरल बनाएं, एफपीओ को ट्रेनिंग और बैंकिंग से जोड़ें तथा ब्याज दरों में कमी लाएं, ताकि किसान और उद्यमी आसानी से निवेश कर सकें।कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र है, जहां 86 प्रतिशत भूमि सिंचित है। किसानों को निःशुल्क बिजली, निःशुल्क नहर सिंचाई और सोलर पैनल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे खेती की लागत कम हो रही है और किसान अधिक निवेश के लिए प्रेरित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार पांच वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है।

चुनाव आयोग को भाजपा का पर्याय बना दिया गया है : अखिलेश यादव

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि उल्टा यह कहना पड़ेगा कि अगर चुनाव आयोग का कोई झंडा हो, तो वह भाजपाइयों के घरों पर लगा देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब बस यही बचा है कि चुनाव आयोग भाजपाइयों के घरों पर ही बूथ बना दे और भाजपाइयों को ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दे।अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर यह स्थिति कैसे बन गई कि क्या चुनाव आयोग ने भाजपा को ठेके पर अपना काम दे दिया है या फिर भाजपा ने चुनाव आयोग को संविदा पर रख लिया है। उन्होंने कहा कि आज देश में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी निष्पक्षता को लेकर गंभीर संदेह उत्पन्न हो रहा है।सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासनिक पर्यायवाची कोश में अब 'चुनाव आयोग' को 'भाजपा' के पर्यायवाची के रूप में जोड़ देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट भाजपा शासनकाल में अब यह आश्चर्य की बात नहीं रह गई है कि सरेआम वोट काटने और बढ़ाने जैसे अपराध हो रहे हैं, बल्कि आश्चर्य इस बात का है कि संवैधानिक संस्थाओं को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज जो लोग वोट छीन रहे हैं, वे कल जनता का बाकी सब भी छीन लेंगे और उस स्थिति में भाजपाई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं बचेगा।अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि ठगों का रिश्ता सिर्फ ठगी से होता है, किसी और से नहीं। उन्होंने

गर निगम लखनऊ में 06 फरवरी को संपूर्ण समाधान दिवस, महापौर करेंगी अध्यक्षता

लखनऊ। शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ द्वारा शुक्रवार, 06 फरवरी 2026 को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को आयोजित किए जाने की परंपरा के अंतर्गत यह कार्यक्रम नगर निगम मुख्यालय, लालबाग स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संपन्न होगा।संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता महापौर सुषमा खर्कवाल द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम के विभिन्न विभागों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे और यथासंभव उनका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य है कि आमजन को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और एक ही मंच पर उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

नगर निगम मुख्यालय में मृतक आश्रितों को मिला सहारा, महापौर ने 13 को सौंपे नियुक्ति पत्र

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ मुख्यालय में गुरुवार को एक गरिमामयी और संवेदनशील कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर सुषमा खर्कवाल द्वारा मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। यह कार्यक्रम उन परिवारों के लिए राहत और संबल का संदेश लेकर आया, जिन्होंने नगर निगम की सेवा के दौरान अपने परिजनों को खो दिया था। नगर निगम द्वारा मृतक आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और मानवीय कदम माना जा रहा है।कार्यक्रम के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल ने कुल 13 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें शेखर, आकाश कुमार भारती, सुभाष धानुक, नीरज कुमार, शिवांशू भारती, काजल और शिवम भारती शामिल हैं। इन सभी मृतक आश्रितों को नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त किया गया है, जिससे उन्हें नियमित आय के साथ सम्मानजनक आजीविका का अवसर मिल सकेगा।इस अवसर पर रागिनी, विकास भारती, बीनू, रितिक गहरवाल, अवनीश कुमार, पिन्की, महापौर ने नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर निगम अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों को नौकरी देना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों को सम्मान, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम है, जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। महापौर ने नवनियुक्त कर्मियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी पी.के. श्रीवास्तव, प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान विकास सिंह सहित नगर निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा नवनियुक्त कर्मचारियों को विभागीय नियमों, कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियों की जानकारी भी दी गई, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारु रूप से कर सकें।अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने बताया कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी।

नगराम क्षेत्र में माइनर नहर से युवक का शव बरामद, नशे की हालत में फिसलकर गिरने से मौत की आशंका

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। थाना नगराम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हसनपुर के पास स्थित माइनर नहर में गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर जांच शुरू की। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में यह मामला दुर्घटनावश मृत्यु का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।पुलिस के अनुसार 05 फरवरी 2026 को प्रातः लगभग 09 बजे थाना नगराम पर ग्राम हसनपुर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के समीप माइनर नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय निवासियों से पूछताछ की गई। उपलब्ध तथ्यों और ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मृतक की प्रथमदृष्टया पहचान शैलेंद्र कुमार पुत्र गंगा प्रसाद, निवासी पान कुंवर खेड़ा, हिलौली, थाना मौरावां, जनपद उन्नाव के रूप में हुई है। मृतक की उम्र लगभग 26 वर्ष बताई गई है।पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों से संपर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि शैलेंद्र कुमार अविवाहित था। उसकी भाभी का मायका ग्राम कनेरी, थाना नगराम क्षेत्र में है, जहां वह पूर्व में भी आता-जाता रहा है। मृतक के परिवार में उसकी माता एवं दो बड़े भाई हैं, जो विवाहित हैं।शव के बाह्य निरीक्षण में प्रथमदृष्टया शरीर पर किसी प्रकार के स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। विधिक प्रक्रिया के तहत मौके पर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सके।घटनास्थल के निरीक्षण तथा उपलब्ध प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि मृतक नशे की

अंतिम पंक्ति तक गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य कैंपों के आयोजन के लिए चिकित्सकों का दल रवाना हो रहा है। यह कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, जो डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध एवं गोरक्ष प्रांत तथा गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास द्वारा आयोजित गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा भारत-नेपाल सीमा से सटे थारू बाहुल्य क्षेत्रों में जनसेवा का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। इस यात्रा के अंतर्गत महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती एवं बहराइच जनपदों में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि छह फरवरी से आठ फरवरी तक इन जनपदों में चिकित्सकीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।स इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने थारू बाहुल्य जनपदों की ओर रवाना होने वाली बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे यह सेवा अभियान संगठित एवं सुचारु रूप से धरातल पर पहुंचेगा। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों को विश्व की सबसे छोटी ईसीजी मशीन "स्पंदन ईसीजी मशीन" का वितरण भी किया गया। डिप्टी सीएम ने बताया कि यह मशीन बिना बैटरी और इंटरनेट के भी कार्य करने में सक्षम है। अत्याधुनिक तकनीक से युक्त यह उपकरण दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में त्वरित एवं सटीक जांच को संभव बनाकर जनस्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाएगा।ब्रजेश पाठक ने कहा कि सेवा, समर्पण और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित यह पहल 'सबका स्वास्थ्य, सबका सम्मान' के संकल्प को सशक्त करती है। उन्होंने इस पुनीत अभियान से जुड़े सभी चिकित्सकों, आयोजकों और स्वयंसेवकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होंगे।कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वांत रंजन, प्रांत प्रचारक कौशल, विशेष संपर्क प्रमुख प्रशांत भाटिया, राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह, प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप तिवारी सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, स्वयंसेवक और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

प्रतापगढ़ में पं. दीनदयाल उपाध्याय कन्वेंशन हाल निर्माण को मिली तीसरी किश्त, एक करोड़ रुपये स्वीकृत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास भवन परिसर में पं. दीनदयाल उपाध्याय कन्वेंशन हाल (अनावासीय भवन) के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में तृतीय किश्त के रूप में एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।जारी शासनादेश में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कन्वेंशन हाल का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप ही कराया जाए। निर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य स्वीकृत लागत के अंतर्गत तथा निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जाएगा और इसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी। शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय अनिवार्य रूप से चालू वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि परियोजना की प्रगति में किसी प्रकार की देरी न हो। अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।उल्लेखनीय है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय कन्वेंशन हाल के निर्माण के लिए पूर्व में 532.10 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में 291.05 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

मंत्री ए.के. शर्मा का मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, सीएचसी स्तर की सुविधाएं विकसित करने का आश्वासन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने मऊ भ्रमण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन का आकस्मिक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा मौके पर उपस्थित चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार, दवाओं एवं सुविधाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त की।निरीक्षण के समय मंत्री ने ओपीडी कक्ष, दवा वितरण कक्ष, उपचार कक्ष, प्रतीक्षालय सहित स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न विभागों का अवलोकन किया। उन्होंने उपलब्ध दवाओं की स्थिति, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, जांच सुविधाओं और साफ-सफाई व्यवस्था की गहन समीक्षा की। मंत्री ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों के साथ संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और व्यवस्था में निरंतर सुधार आवश्यक है।निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सीमित सुविधाओं की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्हें और बेहतर किए जाने की मांग रखी। इस पर मंत्री ए.के. शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन को शीघ्र ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की सुविधाओं से युक्त किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सीएचसी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होने से क्षेत्रीय लोगों को बेहतर उपचार, जांच और आपातकालीन सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी, जिससे उन्हें गंभीर इलाज के लिए दूर-दराज के जिलों में नहीं जाना पड़ेगा।मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि हर व्यक्ति को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए, ताकि मधुबन क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

संत रविदास के विचार समाज को मानवता और समरसता का मार्ग दिखाते हैं: मंत्री ए.के. शर्मा

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ जनपद भ्रमण के दौरान उसुरी कुटी, मधुबन में संत शिरोमणि रविदास की जयंती पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज के प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास अत्यंत विलक्षण संत थे, जिनके विचारों को पूरा देश नमन करता है।

बकाया संपत्तिकर न चुकाने पर नगर निगम सख्त, नवीन गल्ला मंडी सीतापुर रोड का बैंक खाता सीज

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ ने संपत्तिकर की बकाया राशि जमा न करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव के निर्देश पर जोन-6 अंतर्गत सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी से संबंधित भवनों पर लंबे समय से बकाया संपत्तिकर की वसूली न होने पर मंडी समिति का बैंक खाता सीज कर दिया गया है। नगर निगम की इस कार्रवाई से कर बकाया रखने वाली संस्थाओं में हड़कंप मच गया है।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, नवीन गल्ला मंडी सीतापुर रोड, लखनऊ स्थित भवन संख्या जीबी/सीसी पर 31 मार्च 2026 तक कुल 42 लाख 36 हजार 118 रुपये का संपत्तिकर बकाया है। इसके अतिरिक्त मंडी से जुड़े भवन संख्या 605/385 पर 22 लाख 57 हजार 922 रुपये की संपत्तिकर राशि अब तक जमा नहीं की गई है। इस प्रकार दोनों भवनों पर कुल मिलाकर भारी मात्रा में संपत्तिकर बकाया है, जिसका भुगतान नगर निगम को लंबे समय से नहीं किया गया।नगर निगम प्रशासन ने बताया कि बकाया संपत्तिकर की वसूली के लिए संबंधित संस्था को पूर्व में कई बार बिल एवं नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क कर बकाया राशि जमा करने के लिए भी कहा गया, लेकिन इसके बावजूद मंडी समिति द्वारा भुगतान नहीं किया गया। जनवरी 2026 में नवीन गल्ला मंडी कार्यालय की ओर से 19 जनवरी 2026 का 22 लाख रुपये का एक चेक व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था, जो बिना हस्ताक्षर का था। यह चेक न तो विधिसम्मत था और न ही नगर निगम कार्यालय में विधिवत रूप से जमा कराया गया। इसके बाद भी संबंधित संस्था की ओर से बकाया राशि के भुगतान को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई।लगातार बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए नगर निगम ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506 से 509 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सख्त निर्णय लिया। इसके तहत मंडी समिति सीतापुर रोड के बैंक खाते को तत्काल प्रभाव से अटैच करते हुए सीज कर दिया गया है और खाते से किसी भी प्रकार के लेन-देन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया संपत्तिकर की पूरी राशि नगर निगम कोष में जमा नहीं कराई जाती है, तो सीज किए गए बैंक खाते से सीधे नगर निगम के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

भारत को तुर्की से सीखना चाहिए

भारत के सामने एक मॉडल तुर्किए का है, जिसने न सिर्फ अपने को अपनी हथियार जरुरतों में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों को ड्रोन सहित अपने हथियार बेच रहा है। उसने पिछले 40 साल में इतने सुनियोजित तरीके से यह काम किया है कि भारत को उससे सीखना चाहिए। भारत ने भी देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्किए से मिले ड्रोन से पाकिस्तान लड़ रहा था। अब भी उसी के ड्रोन गाहे बगाहे पाकिस्तान सीमा पर दिखते हैं। उसने सातवें दशक में साइप्रस संकट के समय अमेरिका और यूरोप ने उसको हथियार देने पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद ही उसने अपने को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया और 1985 में प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के नाम से एक केंद्रीय संस्था बनाई। उसके बाद पिछले चार दशक में तुर्किए ने अलग ही पहचान बना ली है। भारत भी इस मॉडल पर काम कर सकता है।

इस मॉडल की कुछ खास बातें हैं। जैसे तुर्किए ने दूसरे देशों के साथ जो भी हथियार सौदा किया उसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अनिवार्य शर्त रखी। उसने अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि से हथियारों का सौदा किया तो उसके लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखी। उसने स्थानीय इंजीनियरों द्वारा उत्पादन की भी शर्त रखी। सोर्स कोड और डिजाइन पर अधिकार किया और लडाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर और गाइडेड मिसाइल जैसी कई चीजों के उत्पादन का लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद उसने ड्रोन क्रांति की, जिसमें निजी कंपनियों को शामिल किया। रक्षा उत्पादन में भी तुर्किए ने पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया। लेकिन ड्रोन का पूरा क्षेत्र निजी कंपनियों को दिया और यह सुनिश्चित किया कि वे उत्पादन करें, बिकवाने की गारंटी उसकी होगी। यानी तुर्किए उनके लिए बाजार और ग्राहक जुटाएगा। आज स्थिति यह है कि अपनी रक्षा जरुरतों के मामले में तुर्किए 80 फीसदी आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं तुर्किए आज 180 देशों को अपने हथियार बेचता है। पूरा अफ्रीका उसका बाजार है। वह मध्य एशिया, खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप को भी हथियार बेचता है। उसने देश के कई हिस्सों में डिफेंस प्रोडक्शन के कलस्टर बनाए हैं, जहां उत्पादन होता है।

भारत अगर आज इस मॉडल पर चलना शुरू होता है तो अब तकनीक और उत्पादन की रफ्तार दोनों इतनी तेज हो गई है कि उसे तुर्किए की तरह 40 साल नहीं इंतजार करना होगा। वह सिर्फ 10 साल में अपनी जरुरतों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा और दुनिया के रक्षा से जुड़े उत्पाद बेचने लगेगा। भारत के पास पहले से डीआरडीओ और अन्य पीएसयू हैं, जो रक्षा उपकरण बना रहे हैं। भारत जो व्यापारिक संधियां कर रहा है उसमें प्रौद्योगिक हस्तांतरण, लाइसेंस्ड प्रोडक्शन, लोकल इंजीनियर और लोकल प्रोडक्शन, सोर्स कोड व डिजाइन पर कंट्रोल आदि की शर्तें रखवाता है और निजी व सरकारी कंपनियों को इस काम में शामिल करता है तो बहुत जल्दी भारत में भी एक बड़ा मिलिट्री डिफेंस कॉम्प्लेक्स विकसित हो सकता है। इसके अलावा भारत के पास इसरो के रूप में एक ऐसी संस्था है, जिसने पहले से पूरी दुनिया में अपना बाजार बनाया है। उसको राजनीति में घसीटने की बजाय उसे और मजबूत बनाया जाए तो वहां से दुनिया भर के सेटेलाइट लॉन्च होंगे, जिनसे भारत को आय होगी।

भारत की बड़ी समस्या यह है कि यहां के अरबपति, खरबपति सब यही के 140 करोड़ लोगों की जेब से पैसे निकालने और सरकारी व प्राकृतिक संपदा का दोहन करके अपना खजाना भरने में लगे हैं। वे शोध व विकास यानी आरएंडडी पर धेला खर्च नहीं करते हैं। वे कोई जोखिम नहीं लेते हैं। उनकी सारी कमाई दुनिया की बड़ी कंपनियों का माल बेच कर है या सरकारी ठेके हासिल करने से है। सरकार खुद भी आरएंडडी पर बहुत कम खर्च करती है। सरकार रिसर्च पर अपना खर्च बढ़ाए, शिक्षण संस्थाओं को बेहतर करे और निजी सेक्टर को निवेश करने के लिए प्रेरित करे तब भी भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी और उसके बाद भारत अपना सामान बाहर बेचने लायक बनेगा।

सिर्फ समझौता नहीं, हमारे भविष्य का रोडमैप है भारत-यूरोपीय संघ एफटीए

यह एफटीए नियम आधारित व्यापार और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करता है जिससे भारत स्वदेशी और विदेशी निवेश के लिए और ज्यादा आकर्षक बनेगा।

पीयूष गोयल

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे तथा भारतीय युवाओं और किसानों के लिए व्यापक अवसरों का सृजन होगा। इसके साथ ही लगभग 2 अरब की उस आबादी के लिए धन पैदा होगा जो मिल कर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक-चौथाई भाग है।

विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह एफटीए इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक है। वास्तव में यह व्यापार समझौते से ज्यादा व्यापक है। यह कृत्रिम मेधा (एआई), रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने वाली विस्तृत साझीदारी है। इस एफटीए से भारत के हर क्षेत्र और नागरिक तथा खास तौर से निर्धन तबकों को लाभ पहुंचेगा।

यह एफटीए नियम आधारित व्यापार और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करता है जिससे भारत स्वदेशी और विदेशी निवेश के लिए और ज्यादा आकर्षक बनेगा। यह छोटे व्यवसायियों, स्टार्टअप संस्थाओं और कामगारों के लिए अनेक अवसर पैदा करेगा।

विश्व ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा की सराहना करते हुए इस एफटीए को सभी समझौतों से बड़ा बताया है। यह वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में स्थिरता को मजबूत करता है। यह भारत और यूरोपीय संघ को मुक्त बाजार, पूर्वानुमान क्षमता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध भरोसेमंद साझीदारों के रूप में स्थापित करता है।

भारत ने व्यापार मूल्य के हिसाब से यूरोपीय संघ में अपने 99 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्राप्त की है जिससे 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल मिलेगा। इस एफटीए से कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरी सामान और ऑटोमोबाइल जैसे श्रमसाध्य क्षेत्रों को निर्णायक मजबूती मिलेगी।

इस समझौते से लगभग 33 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत तक टैरिफ खत्म होगा। इससे कामगारों, हस्तशिल्पियों, महिलाओं, युवाओं तथा सूक्ष्म, छोटे और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) का सशक्तीकरण होगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला से भारतीय व्यवसाय ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी।

यह समझौता व्यवसायियों और पेशेवर तबके के लिए दूसरे देशों में जाने को आसान बनाते हुए शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और कंप्यूटर जैसे सेवा क्षेत्रों में अवसरों के नए द्वार खोलता है। इन प्रतिबद्धताओं से उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसरों के खुलने के साथ ही प्रतिभा, नवोन्मेष और संवहनीय आर्थिक विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होती है। व्यापार समझौते गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने की मोदी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। इस रणनीति में क्रांतिकारी सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा सभी पक्षों के लिए लाभकारी समझौते के उद्देश्य से विकसित और पूरक अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत शामिल है। यह रणनीति भारत को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने और उन लाभकारी बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाती है जो कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हुए श्रमसाध्य क्षेत्रों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते भारतीय उद्योगों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करते हैं और उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यूपीए सरकार ने बिना सोचे-समझे भारत के बाज़ार खोल दिए थे, इसके उलट मोदी सरकार ने ऐसे समझौते किए हैं जिनमें टैरिफ में कमी धीरे-धीरे की जाती है। जिससे उद्योगों को उचित नीतिगत समर्थन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण का केंद्र है। पिछले सप्ताह इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा थाः आइए, इस साल हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। हमारा एकमात्र मंत्र गुणवत्ता, गुणवत्ता और केवल गुणवत्ता होना चाहिए। कल की तुलना में आज और बेहतर गुणवत्ता। हम जो कुछ भी बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने का संकल्प लें।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के पूरी तरह अनुरूप है। यह भारत को वैश्विक मंच पर एक गतिशील, विश्वसनीय और दूरदर्शी भागीदार के रूप में स्थापित करता है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए समावेशी, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार विकास की नींव रखता है। मोदी सरकार ने सिर्फ़ विकसित देशों के साथ ही व्यापार समझौते किए हैं, जो कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, और हस्तशिल्प जैसे भारत के प्रमुख रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यह यूपीए शासन से बिल्कुल उल्टा है उन्होंने प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के साथ समझौतों में जल्दबाजी की और अक्सर भारत को मिलने वाले लाभ की तुलना में कहीं अधिक रियायतें दीं।

इसके अलावा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यूपीए सरकार ने व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले हितधारकों के साथ कोई सार्थक बातचीत की थी। इसके विपरीत, मोदी सरकार ने अर्थशास्त्रियों, औद्योगिक निकायों, विशेषज्ञों और कई सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद ही मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। परिणामस्वरूप, मोदी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक व्यापार समझौते को उद्योगों से व्यापक सराहना मिली है। मोदी सरकार द्वारा संपन्न प्रत्येक मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों पक्षों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं और भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार किया है। इन समझौतों ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनने की दिशा में उसकी यात्रा को तेज़ किया है।

यूपीए के कार्यकाल के दौरान, यूरोपीय संघ सहित विकसित देशों की भारत में रुचि कम हो गई थी, क्योंकि आर्थिक विकास धीमा हो गया था, मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई थी और व्यापार का माहौल निराशाजनक था। तब भारत ने ऐसे लाभप्रद व्यापार समझौतों के मूल्यवान अवसर गंवा दिए, जो विकास को गति दे सकते थे और रोजगार पैदा कर सकते थे।

मोदी सरकार द्वारा संपन्न अन्य व्यापार समझौतों के साथ, भारत-ईयू एफटीए, दुलमुल और निर्णायक नेतृत्व के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। जहाँ पहले की सरकारें हिचकिचाती थीं और घुटने टेकती थीं वहीं मोदी सरकार ने बदलाव लाने वाला एक ऐसा समझौता किया है जो बाजारों का विस्तार करने के साथ साथ रोजगार पैदा करता है और भारत के मुख्य हितों की रक्षा करता है। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक स्पष्टता नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है, जो देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकते हैं।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)

टिप्पणी

केंद्र के अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति उज्जल भूइंया ने यह सटीक प्रश्न उठाया है कि किसी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए क्यों तबादला होना चाहिए कि उसने सरकार के लिए कोई 'असुविधाजनक निर्णय' दिया हो?

जब संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का विवादित तबादला चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट ने जज उज्जल भूइंया ने उच्चतर न्यायपालिका के जजों के तबादले के पीछे की राजनीतिक कहानी पर से परदा हटा कर काफी कुछ उजाले में ला दिया है। न्यायमूर्ति भूइंया ने पूछा कि किसी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए क्यों तबादला होना चाहिए कि उसने सरकार के लिए कोई 'असुविधाजनक निर्णय' दिया हो? हालांकि न्यायमूर्ति ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि उनका इशारा बीते अक्टूबर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज अतुल श्रीधरन के तबादले की ओर था।

जस्टिस श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मध्य प्रदेश के एक मंत्री के बयान का संज्ञान लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पहले उनका तबादला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट किया, लेकिन तुरंत ये फैसला बदल कर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब साफ है कि ऐसा केंद्र के अनुरोध पर किया गया। आम चर्चा है कि इस रूप में सरकार कॉलेजियम के तबादला संबंधी कई फैसलों के प्रभावित कर चुकी है। और जब उच्चतर न्यायपालिका में ये हाल हो, तो निचली अदालतों के बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सीजेएम सुधीर ने संभल की हिंसा के मामले में पुलिस अधिकारी पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। उसके कुछ ही दिन बाद उनका तबादला हो गया।

जस्टिस भूइयां ने उचित चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाएं भारतीय न्यायपालिका की साख पर बट्टा लगा रही हैं। उन्होंने कहा- 'अगर हमने अपनी साख खो दी, तो न्यायपालिका में कुछ नहीं बचेगा। जज रहेंगे, अदालतें भी रहेंगी, मुकदमों पर फैसले भी होंगे, लेकिन दिल और आत्मा का लोप हो जाएगा।' तमाम जजों को न्यायमूर्ति भूइयां की इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि न्यायापालिका के पास ना तो धन होता है, ना तलवार। उसमें लोगों का भरोसा ही उसकी कुल जमा-पूंजी है। बड़े परिदृश्य में देखें, तो मुद्दा सिर्फ न्यायपालिका नहीं है। सबको इसका ख्याल रखना चाहिए कि इसकी साख चूकने का अर्थ पूरी शासन व्यवस्था के औचित्य को संदिग्ध कर देगा।

ब्लॉग

शिक्षक अब पाठ्येत्तर कार्यों के लिए हैं

अजीत द्विवेदी

शिक्षक का मूल कार्य अध्ययन और अध्यापन है। भारत के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अध्ययन का काम पहले ही काफी हद तक छोड़ चुके थे और अब अध्यापन का काम भी नाममात्र का रह गया है। शिक्षक अब स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि पाठ्येत्तर कार्यों के लिए हैं। उनके ऊपर इतने कामों की जिम्मेदारी लाद दी गई है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर लगातार कम होता जा रहा है तो इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि शिक्षक अच्छे नहीं हैं या शिक्षकों के प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वह कई कारणों में से एक कारण है। असल में सरकारी स्कूलों की कार्यों की सूची में अध्यापन का कार्य प्राथमिकता में नहीं है। उन्हें स्कूल से बाहर और स्कूल में भी कई दूसरे काम करने हैं, जिनका पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के शिक्षक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में लगे हैं। कुछ राज्यों के शिक्षक स्थानीय निकायों के चुनाव करा रहे हैं। इस साल और अगले साल दो चरणों में जनगणना का काम होगा और शिक्षक उसमें लगा दिए जाएंगे। पांच राज्यों के चुनाव भी हैं तो मतदान कराने से लेकर मतगणना तक उन राज्यों के सरकारी शिक्षक उसमें व्यस्त हो जाएंगे। वैसे उन राज्यों के स्कूल भी चुनाव के लिए आरक्षित होंगे। कहीं सुरक्षा बलों को ठहराया जाएगा तो कहीं मतदान केंद्र बनेंगे तो कहीं मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण या मतदान और मतगणना या जनगणना जैसे कामों की सूची बेहद लंबी है, जो शिक्षकों को करना होता है। एक अनुमान के मुताबिक अध्ययन और अध्यापन के अलावा शिक्षकों को स्कूल के बाहर डेढ़ दर्जन किस्म के अन्य सरकारी काम करने होते हैं। एक शिक्षक ने तंज करते हुए सोशल मीडिया में लिखा था कि अच्छा है कि सरकार खेती नहीं कराती है अन्यथा बुवाई, कटाई का काम भी शिक्षकों को करना होता।

बहरहाल, सरकार परिवार और स्वास्थ्य का सर्वे करती है तो वह काम शिक्षक करते हैं, सरकार पशुओं की गिनती कराती है तो वह काम शिक्षक करते हैं, सरकार किसी आपदा की स्थिति में राहत सामग्री बांटती है तो वह काम भी शिक्षकों के जिम्मे होता है, किसी बीमारी या टीके के लिए जागरूकता फैलानी है तो उसका जिम्मा भी शिक्षकों के ऊपर होता है, सफाई अभियान चलाना है तो उसमें शिक्षकों को आगे किया जाता है, यहां तक कि सत्तापक्ष के किसी बड़े नेता की रैली होती है तो उसमें भी शिक्षकों को बस में भर कर रैली में जाना होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा जिले के कलेक्टर, प्रखंड के बीडीओ और पंचायत के मुखिया भी शिक्षकों को किसी न किसी काम में लगाए रहते हैं।

स्कूल के बाहर शिक्षकों को जो डेढ़ दर्जन अलग अलग किस्म के काम करने होते हैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि बचे हुए समय में उनको स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। स्कूल में उनको डेढ़ दर्जन अलग किस्म के काम करने हैं, जो अध्ययन और अध्यापन से इतर हैं। मिसाल के तौर पर मिड डे मील तैयार करना एक काम होता है। एक से ज्यादा शिक्षक तो इसी में लगे रहते हैं। राशन खरीदने से लेकर खाना तैयार कराना और बच्चों को खिलाना स्कूलों में प्राथमिकता का काम है। जब से सरकार को लगने लगा है कि मास्टर लोग राशन में गड़बड़ी करते हैं तब से गड़बड़ी नहीं होने के सबूत जुटाना यानी हर चीज का हिसाब रखना, वीडियो आदि बनाना, डैशबोर्ड पर अपलोड करना भी शिक्षकों का जिम्मा हो गया है। एक समय सरकार को लगा कि बच्चे सिर्फ खाने आते हैं या बच्चों की असली संख्या कम होता है और ज्यादा बच्चों के लिए खाना बनाने के नाम पर पैसे की गड़बड़ी होती है तब से शिक्षकों को यह काम भी दिया गया कि वे मिड डे मील खाने वाले बच्चों का फेशियल रिकग्निशन करें और उनकी वीडियो तैयार करें ताकि पुष्टि हो सके कि जिस बच्चे का नाम रॉल में है उसने स्कूल में खाना खाया। सो, मिड डे मील का मामला अब राशन खरीदने, खाना बनवाने और खिलाने के काम से काफी आगे बढ़ गया है। इस बीच तमिलनाडु सहित 12 राज्यों ने प्रस्ताव दिया है कि अगर स्कूलों में बच्चों को सुबह का नाश्ता भी दिया जाए तो उनका बेहतर पोषण होगा, उपस्थिति बढ़ेगी और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को इसे भी लागू कर ही देना चाहिए ताकि शिक्षकों को पढ़ाने के काम से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए।

ऐसा नहीं है कि इतने पर भी शिक्षकों की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। उन्हें और भी कई काम करने होते हैं। मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री शिक्षा से जुड़े किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हैं तो स्कूलों से कहा जाता है कि उनका भाषण बच्चों को सुनाया जाए ताकि वे 'लाभान्वित हो सकें। केंद्रीय विद्यालयों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुनाया जाता है तो राज्यों के स्कूलों में राज्य के शिक्षा मंत्री का भाषण सुनाया जाता है। प्रधानमंत्री का भाषण तो सभी स्कूलों में सुनाया जाता है। भाषण सुनाने की व्यवस्था करने में कम से कम दो कक्षाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन इतने पर काम खत्म नहीं होता है।

भाषण सुनते बच्चों की वीडिया बना कर उनको ऊपर भेजना होता है और किसी निर्धारित पोर्टल पर अपलोड भी करना होता है। यह काम हर सरकारी फंक्शन के बाद करना होता है। राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम हो या नवाचार के नाम पर शुरू की गई किसी पहल का कार्यक्रम हो। उसे आयोजित करना, उसकी वीडियो बनाना और उसे अपलोड करना शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। शिक्षकों को इवेंट मैनेजर बना दिया गया है। उनको कार्यक्रम आयोजित करने, उसे सफल बनाने और उसके वीडियो अपलोड करने से फुरसत नहीं मिलती है। ग्रामीण और छोटे कस्बों में तो ज्यादातर स्कूल दो या तीन शिक्षकों के साथ चलते हैं। उन स्कूलों में तो शिक्षकों को पढ़ाने की फुरसत कभी नहीं मिल पाती है।

एनसीईआरटी के निदेशक रहे देश के जाने माने शिक्षाविद् प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने दो महीने पहले 'एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'इन इंडिया, व्हाई टीचर्स आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द क्लासरूम। इसमें उन्होंने यूनेस्को की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसका टाइटल 'व्हेअर हैव ऑल द टीचर्स गॉन था। इसमें यूनेस्को ने दुनिया भर में उभर रहे एक ट्रेंड का हवाला दिया था। दुनिया भर के देशों में पिछले दो दशक में अलग अलग कारणों से शिक्षक अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी नौकरी मिलने पर वे शिक्षक की नौकरी छोड़ रही हैं। वे स्कूलों में नौकरी करने की बजाय बेरोजगारी और अनिश्चितता का भविष्य चुन रहे हैं। यह बहुत भयावह ट्रेंड है। ऐसा करने के कई कारणों में एक कारण स्कूलों में बच्चों का बदलता व्यवहार भी है।

अच्छे शिक्षकों के लिए अब बच्चों को स्कूलों में हैंडल करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। एक कारण स्कूलों की दशा भी है। लेकिन एक बड़ा कारण नौकरशाही है, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा प्रबंधन के काम में लगा दिया गया है। उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने हैं, कार्यक्रमों की वीडियो बनानी है, उन्हें सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना है, अलग अलग कार्यों की रिपोर्ट तैयार करनी है, उस रिपोर्ट को सरकारी दफ्तरों में भेजना है, नेताओं व अधिकारियों के भाषण सुनने हैं, उन भाषणों में कही गई उलजुलूल बातों को स्कूल में बच्चों को बताना है, इन सब कारणों से अच्छे शिक्षकों का मोहभंग हो रहा है। वे स्कूल छोड़ रहे हैं। जो बचे रह जा रहे हैं वे अध्ययन या अध्यापन का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नौकरी कर रहे हैं।

शिक्षकों को क्लर्क या मैनेजर बना दिया गया है। उन्हें बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। उन्हें बच्चों में रचनात्मकता लाने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। उन्हें बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देने की बजाय प्रबंधकीय कार्यों में लगाया जाता है। उनको मजबूर किया जाता है कि वे प्रबंधकीय कार्यों का सबूत इक_ा करें नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। उन्हें बच्चों को पढ़ाने और जीवन संघर्षों के लिए तैयार करने की बजाय इस पर ज्यादा ध्यान देना होता है कि डैशबोर्ड पर बने चेक लिस्ट में कितने खानों में सही का निशान लगा है। उससे उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होती है। सरकारों द्वारा तैयार कराए गए डिजिटल रिसोर्स यूज करने का दबाव शिक्षकों पर होता है। अगर कोई शिक्षक अपनी रचनात्मकता दिखाना चाहे तो उसके लिए कोई स्पेस नहीं होता है। इससे अच्छे शिक्षकों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वे नौकरी छोड़ रहे हैं तो बाकी शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में नुकसान बच्चों का है।

इटावा में नीम के पेड़ से 15 दिन से लगातार निकल रहा दूध जैसा पदार्थ, लोग कर रहे पूजा

आर्यावर्त संवाददाता

इटावा। इटावा जिले के जसवंतनगर क्षेत्र के जल पोखरा गांव में एक अजीब घटना सामने आई है। यहां एक नीम के पेड़ से दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलने की घटना की चारों ओर चर्चा हो रही है। करीब 15 दिनों से लगातार निकल रहे इस तरल पदार्थ को लोग आस्था से जोड़ रहे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु पेड़ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। पेड़ के पास भजन कीर्तन हो रहे हैं और इतना ही नहीं लोग इसे बीमारियों में लाभकारी मानकर सेवन भी कर रहे हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देख रहे हैं।

इलाके में जमुना बाग के पास जल पोखरा गांव में उस समय हलचल मच गई, जब एक ढाबे के पीछे स्थित नीम के पेड़ से सफेद तरल पदार्थ निकलता दिखाई दिया।

यह नीम का पेड़ अजय कुमार के खेत में बताया गया है। दिन के समय इस तरल पदार्थ को पेड़ से टपकता देखा गया, जिसके बाद गांव में इसकी चर्चा तेजी से फैल गई।

पेड़ की पूजा कर रहे लोग

सूचना फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते यह जगह लोगों की भीड़ से भर गई। कई लोगों ने इस तरल को चमत्कार मानते हुए इसे देवी माता की कृपा बताया। वहीं महिलाओं को पेड़ के पास भक्ति गीतों पर झूमते और पूजा करते देखा गया।

तरल पदार्थ का सेवन कर रहे लोग

नीम का यह पेड़ अब पूजा पाठ और प्रसाद वितरण का केंद्र बन गया है। लोग पेड़ पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। साउंड सिस्टम लगाकर भजन कीर्तन हो रहे हैं। पेड़ से निकलने वाले तरल पदार्थ को लोग प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं और दूसरे स्थानों पर भी इसका सेवन कर रहे हैं। पुजारी धर्मेंद्र शास्त्री का कहना है कि प्रतिदिन 6 से 7 लीटर तरल पदार्थ पेड़ से निकल रहा है। यहां प्रतिदिन 500 से अधिक श्रद्धालु यहां आ रहे है। श्रद्धालु इसको देवी का स्थान मान रहे हैं। लोगों की आस्था है। बाकी क्या है यह, हम लोगों को नहीं पता है।

प्रसाद के रूप में ले जा रहे घर

तरल पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों का कहना है कि इसका स्वाद नारियल पानी जैसा है। कुछ लोगों का दावा है कि इसके सेवन से खुजली और दर्द में राहत मिल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज भी यहां इसे दवा के रूप में लेने के लिए पहुंच रहे हैं।

क्या कहना है कृषि विभाग का?

वहीं कृषि उपनिदेशक का कहना है कि नीम के पेड़ से इस तरह का रस निकलना प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। उनके अनुसार जड़ों पर अधिक दबाव और धूप की कमी के कारण पेड़ों से ऐसा तरल निकलने की संभावना रहती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बावजूद इलाके में आस्था का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि धूप निकलने के बाद यह तरल पदार्थ निकलना बंद हो जाएगा।

सुभारती कॉलेज ऑफ एलाइड एंड हेल्थकेयर में अतिथि व्याख्यान का सफल आयोजन

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। सुभारती कॉलेज ऑफ एलाइड एंड हेल्थकेयर परिसर में प्रातः 10:00 बजे "From Ideas to Assets: Understanding Intellectual Property Rights" विषय पर बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से सम्बन्धित एक ज्ञानवर्धक अतिथि व्याख्यान का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री सिम्मर नायर द्वारा कुशलतापूर्वक संभाला गया।

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. पंकज किशोर मिश्रा, प्राचार्य (एसोसिएट) के शुभोद्घाटन संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन संस्कार संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि वक्ता डॉ. निशा गुप्ता, इन्फ्रो – आईपीआर सॉल्यूशंस सेल एवं रिसर्च व डेवलपमेंट सेल, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.) का पुष्प वेंट कर गरिमा पूर्वक अभिनन्दन किया गया।

डॉ. निशा गुप्ता ने बौद्धिक संपदा अधिकार क्या हैं, उनके प्रकार, पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन तथा अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत एवं सरल भाषा में उपयोगी व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनका व्याख्यान विद्यार्थियों एवं सहभागियों के लिए अत्यन्त ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक साबित हुआ।कार्यक्रम के अंत में डॉ. उमेश कुमार, विभागाध्यक्ष (एमएलटी) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. पंकज किशोर मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के समस्त संकाय सदस्य तथा विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। यह व्याख्यान कार्यक्रम अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल रहा तथा उपस्थित सभी प्रतिभागियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता और समझ को और अधिक सुदृढ़ किया।

मेरठ में एसएसपी की कमान आईपीएस अविनाश पांडेय को

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। शासन ने 2015 बैच के आईपीएस अविनाश पांडेय को मेरठ का एसएसपी नियुक्त किया है। अभी तक उनकी तैनाती लखनऊ एसएसएफ वाहिनी में थी। 2019 में भी अविनाश पांडेय एसपी देहात के पद पर मेरठ में रह चुके हैं। मऊ में तैनाती के दौरान मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।

अविनाश पांडेय को 23 अप्रैल 2025 को पीलीभीत से एसएसएफ वाहिनी लखनऊ में भेजा गया था। उससे पहले भी वह गाजियाबाद के एसपी सिटी और प्रयागराज कुंभ में भी तैनात रहे है। पंजाब में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला कर भागकर पीलीभीत आए तीन खालिस्तानी आतंकियों को पूरनपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराने व फर्जी पासपोर्ट व वीजा पर सिख युवकों को कनाडा भेजने पर सौ से ज्यादा मामले दर्ज

करने को लेकर अविनाश पांडेय खासे चर्चा में रहे थे।

यहां के एसएसपी डा. विपिन ताडा को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट बनाया गया है। विपिन ताडा के साइकिल पर गश्त करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनकी तारीफ की थी। वह बागपत के पूर्व सांसद एवं मुंबई के पूर्व कमिश्नर सतपाल सिंह के दामाद हैं।अविनाश पांडेय ने मेरठ एसपी देहात पद पर रहते हुए चौकीदारों के लिए प्रहरी एप बनाया था। साथ की साइबर अपराध रोकने के लिए देहात के थानों में भी टीम बनाई थी। अविनाश पांडेय ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से किया है।

आइपीएस डा. विपिन ताडा का मेरठ में 19 माह का कार्यकाल शानदार रहा। इस दौरान उन्होंने कपसाड़ में जातीय संघर्ष के हालात को बड़े ही कायदे से कंट्रोल किया। दो बार कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया। तीन बदमाशों को भी मुठभेड़ में मार गिराया। ज्वालागढ़, दादरी कांड के दौरान बिगड़े हालात को भी उन्होंने सूझबूझ से नियंत्रित किया।

'पहले आओ–पहले पाओ'... मेरठ आवास विकास परिषद ने फ्लैट रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई डेट, कीमत 8 लाख से शुरू

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के लोगों के लिए अपना घर खरीदने का सुनहरा मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देश पर मेरठ आवास विकास परिषद ने फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को अब 31 मार्च 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। वह अब नई लास्ट डेट तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। फ्लैट की कीमत 8 लाख रुपए से शुरू है।

योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा परिवारों को अपने आशियाने का सपना पूरा करने का अवसर देना है। मेरठ आवास विकास के अधिकारियों ने बताया कि जागृति विहार एक्सटेंशन में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन

बुकिंग कर सकते हैं।

बुकिंग के समय फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा, जो बाद में मूल राशि में जोड़ दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एफ-32, एफ-57 और एफ-64 श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध हैं, जो निर्माण गुणवत्ता और सुविधाओं के लिहाज से बेहतर माने जा रहे हैं।

एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगी छूट

योजना की खास बात यह है कि एकमुश्त भुगतान करने पर आकर्षक छूट दी जा रही है। यदि उपभोक्ता बुकिंग के बाद 60 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करता है, तो 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं 90 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा। हालांकि किस्तों में फ्लैट लेने वाले आवेदकों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों को कितनी छूट?

आवास विकास परिषद ने फ्लैट देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जो लोग खरीद से पहले मौके पर जाकर फ्लैट देखना चाहते हैं। वह जागृति विहार एक्सटेंशन पहुंचकर फ्लैट देख सकते हैं। इसके अलावा किस्तों पर खरीद की सुविधा भी दी गई है। सामान्य आवेदक 50 प्रतिशत राशि जमा कर कब्जा लें सकते हैं और शेष रकम किस्तों में चुका सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को विशेष सहूलियत देते हुए 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही कब्जा देने का प्रावधान किया गया है। शेष राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से किस्तें लागू होंगी।

कितनी है फ्लैट की कीमत?

फ्लैटों की कीमत 8 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक तय की गई है। एफ-32 फ्लैट की कीमत 8 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि एफ-57 की कीमत करीब 19 लाख रुपये और एफ-64 की कीमत 21 लाख रुपये निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक आवास विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं।

कोरियन एक्टर की दीवानी थीं गाजियाबाद की तीनों बहनें? सुसाइड नोट में लिखा– हम उससे प्यार करते थे...

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस में एक नया मामला सामने आया है। जांच में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कोरियन एक्टर से प्यार करने की बात लिखी है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में लिखा है कि वी आर लव कोरियन। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है, वो सब पढ़ लो क्योकि ये सब सच है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कई एंगल के जांच कर रही है।

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि हम लोग कोरियन से प्यार करते हैं। आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा। लो छुडवाओगे हमसे कोरियन, कोरियन हमारी जान थी, कोरियन पॉप बहुत पसंद है। तुम नहीं जानते थे कि हम उन्हें कितना चाहते थे, लो अब देख लिया सबूत, अब तो यकीन हो गया यहां कि कोरियन हमारी जान है। जितना हम कोरियन एक्टर और उनके पॉप ग्रुप को चाहते थे, उतना हम तुम घरवालो को भी नहीं चाहते थे।

कोरियन तो हमारी जान थी...

सुसाइन नोट में लिखा है कि कोरियर तो हमारी जान थी और शादी के नाम से तो हमारे दिल मे टेंशन होती थी। हम पसंद और प्यार करते थे कोरियन से और शादी इंडिया के आदमी से, कभी नही ऐसे तो हमें खुद से भी हमे उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए हमने खुदखुशी कर ली, सॉरी पापा। सुत्रों को मुताबिक ये सभी बातें सुसाइड नोट में लिखी हैं।

तीनों बहनों ने फ्लैट से कूदकर दे दी थी जान

बीते बुधवार को नौवीं मंजिल के फ्लैट से कथित तौर पर कूदकर तीनों नाबालिग बहनों ने आत्महत्या कर ली थी। तीनों बहनें निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) ने एक सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया था, जिसके काफी फॉलोअर्स थे। उन्होंने खुद को कोरियन नाम – मारिया, एलिजा और सिंडी दिया था।

पुलिस को सुबह करीब 2।15 बजे सूचना मिली कि साहिबाबाद इलाके में टीला मोड़ पुलिस स्टेशन के तहत भारत सिटी के एक टावर में नौवीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से तीन लड़कियों ने छलांग लगा दी है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि लड़कियां ग्राउंड फ्लोर पर गिरी थीं और उन्हें जानलेवा चोटें आई थीं। उन्हें एम्बुलेंस से लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शादी का झांसा देकर चार साल तक मुस्लिम युवती से रेप, अब वादे से मुकरा ढाबा संचालक

मेरठ। नौचंदी क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम युवती ने सिवाया टोल प्लाजा के पास ढाबा चलाने वाले युवक पर चार साल तक शादी का झांसा देकर अपना शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि अब युवक अपने वादे से मुकर गया है और उसकी हत्या की धमकी दे रहा है। शास्त्रीनगर निवासी मुस्लिम संप्रदाय की युवती ब्रहस्पतिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। युवती ने बताया कि चार साल पहले वह इंस्टाग्राम के जरिए बुलंदशहर निवासी एक हिंदू युवक के संपर्क में आई थी। आरोप है कि एक दिन युवक ने युवती को मिलने के लिए बुलाया और गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ने युवती से शादी करने का वादा किया। युवक युवती को अक्सर सिवाया टोल प्लाजा के पास स्थित अपने ढाबे पर ले जाता और वहां उसके साथ संबंध बनाता था।

यूपी में चाइनीज मांझे पर सरकार ने लगाया बैन, मौत होने पर चलेगा हत्या का मुकदमा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पूरे उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। यानी अब उत्तर प्रदेश में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चाइनीज़ मांझे की बिक्री और उपलब्धता को रोकने के लिए प्रदेश भर में सघन छापेमारी अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि चाइनीज़ मांझे के कारण यदि किसी की जान जाती है, तो उसे हत्या की श्रेणी में माना जाएगा और उसी के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश स्तर पर चलने वाले इस अभियान की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाइनीज मांझे के कारण हो रही लगातार मौतों को लेकर बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से सीधे सवाल किया कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद बाजार में चाइनीज़ मांझा आखिर कैसे पहुंच रहा है और इसकी बिक्री कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस पर तुरंत और प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए।

सीएम योगी ने सख्त शब्दों में कहा कि अब चाइनीज़ मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों को अपने-अपने जिलों में सघन छापेमारी अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।

चाइनीज़ मांझे से होने वाली घटनाओं की गंभीरता को बताते हुए अधिकारियों ने जानकारी दी कि बुधवार को लखनऊ में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया गया कि वह काफी देर तक तड़पता रहा। बीते एक साल में इस तरह की आठ घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज़ मांझे की बिक्री और इस्तेमाल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि इस अवैध कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान की जाए, तत्काल कार्रवाई हो और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही, पूरे प्रदेश में चाइनीज़ मांझे की जब्ती के लिए यूपी पुलिस को सख्त और लगातार अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।

यूट्यूबर शादाब जकाती पर साथ काम करने वाली महिला के गंभीर आरोप, कहा– उसने मेरे साथ जबरदस्ती...

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ. यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन पर एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चांदनी उर्फ तबस्सुम नाम की महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जकाती ने उसके साथ वीडियो बनाई, लेकिन न तो उसके पेज को प्रमोट किया और न ही उसके साथ वीडियो बनाने के पैसे दिए। महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

महिला का आरोप है कि उसका पति मजदूरी करता है। उसने पैसे कमाने और अपने सोशल मीडिया पेज को प्रमोट करने के लिए शादाब जकाती से बात की थी। शादाब ने कई वीडियो साथ में बनाए, लेकिन उसके पैसे नहीं दिया। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादाब जकाती करीब डेढ़ साल से उसके साथ ऐसा करता आग रहा है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि शादाब ने डरा

धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। चांदनी ने बताया कि जब इस बात की शिकायत करने के लिए वह शादाब जकाती की पत्नी के पास गई तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की।

महिला ने किया है लव मैरिज

चांदनी का सोशल मीडिया अकाउंट तबस्सुम खान सईद के नाम से है और उसकी शादी सोनू नाम के हिंदू युवक से हुई है। दोनों ने लव मैरिज की है। महिला मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।

पहले भी लग चुके हैं जकाती पर आरोप

पिछले महीने एक युवक ने जकाती पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का शादाब के साथ अफेयर चल रहा है। उसने दावा किया था कि दोनों साथ रह रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि बाद में युवक ने अपने आरोप वापस ले सलिए थे। बाद में एक वीडियो जारी कर युवक ने कहा था कि उसकी पत्नी उसकी मर्जी से शादाब जकाती के साथ रह रही है।

पोक्सो के फर्जी मुकदमे में फंसाकर मांगे पांच लाख, रकम नहीं मिली तो दंपति पर किया हमला

मेरठ। माधवपुरम निवासी दंपति ने नौचंदी क्षेत्र के रहने वाले दंपति और कुछ अन्य दबंगों पर अपने घर में घुसकर खुद पर जानलेवा हमले और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पोक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर आरोपी दंपति उसके पति से पांच लाख की डिमांड कर रहे थे। रकम न देने पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया।

माधवपुरम क्षेत्र के रहने वाले दंपति ब्रहस्पतिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे। महिला ने आरोप लगाया कि नौचंदी क्षेत्र के रहने वाले एक दंपति ने उसके पति के खिलाफ पोक्सो एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। सीओ कैंट द्वारा मामले में जांच करने पर यह मुकदमा झूठा पाया गया। आरोप है कि इस मुकदमे को वापस लेने की एवज में दंपति ने महिला के पति से पांच लाख की डिमांड की। मगर महिला के पति ने रकम देने से इनकार कर दिया।

इंस्टाग्राम पर देख हुई दीवानी... रायबरेली में 4 बच्चों की मां 20 साल के प्रेमी के साथ फरार

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। रायबरेली जिले में सरैया मजरे टेकारी दांदू गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चार बच्चों की मां सन्नो देवी अपने 20 वर्षीय प्रेमी से साथ फरार हो गई। दोनों में इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के बीच काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। घटना जिले के डीह थाना क्षेत्र की है।

पीड़ित पति राजेश के अनुसार, 16 दिसंबर को उसकी पत्नी डेढ़ साल की बेटी को साथ लेकर घर से चली गई और तब से लापता है। काफी तलाश के बाद भी जब पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला, तो उसने पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। राजेश ने पत्नी के प्रेमी पर उसे बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। पीड़ित ने बताया

कि दोनों के बीच कई महीनों बातचीत चल रही थी।

पत्नी की तलाश में परेशान राजेश अपने मासूम बच्चों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की मांग की। उसका कहना है कि बच्चों की देखभाल करना उसके लिए मुश्किल हो गया है और परिवार पूरी तरह टूट चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लापता महिला व युवक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिल- प्रशासन ने पीड़ित को जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पहले भी आ चुका है जिले में ऐसा मामला

इंस्टाग्राम पर दोस्ती और प्यार का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटना जिले में हो चुकी है। बीते साल दिसंबर में जिले के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दिल्ली की एक लड़की से दोस्ती की थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और लड़की युवक के मिलने रायबरेली पहुंची गई और शादी करने की जिद पर अड़ गई। जब युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो लड़की ने जहर खा लिया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। इलाज के लिए लड़की को आसपास के लोगों ने अस्पलात में भर्ती कराया था और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया था।

कैंसर और दिल की बीमारियों से बचा सकती है ब्रोकली, पर इसके साइड-इफेक्ट्स भी कम खतरनाक नहीं

फिटनेस इंफ्लुएंसर से लेकर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट तक, सभी ब्रोकली को सुपरफूड का दर्जा दे चुके हैं। पर इसके सेवन को लेकर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं क्योंकि इसके कई प्रकार के साइड-इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।

भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करना सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। पौष्टिक आहार से न सिर्फ हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है बल्कि ये आपको बीमारियों से बचाए रखने में भी सहायक है। जब भी बात पोषक तत्वों से भरपूर आहार की होती है तो ब्रोकली फिटनेस के शौकीन लोगों की पसंदीदा चीजों में से एक मानी जाती है।

फिटनेस इंफ्लुएंसर से लेकर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट तक, सभी ब्रोकली को सुपरफूड का दर्जा दे चुके हैं। असल में, ब्रोकली सिर्फ एक सब्जी भर नहीं है ये पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें मौजूद सल्फोराफेन जैसे तत्व कैंसर से बचाव में मदद करते हैं, वहीं इसका फाइबर और विटामिन्स दिल, पाचन और इम्युनिटी के लिए वरदान हैं।

लो कैलोरी, ज्यादा पोषण और ढेरों फायदों वाली ब्रोकली को भोजन की थाली में शामिल करके आप भी कई लाभ पा सकते हैं। हालांकि इसके सेवन को लेकर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं क्योंकि इसके कई प्रकार के साइड-इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।

पहले ब्रोकली से होने वाले फायदों को जान लीजिए

ब्रोकली पोषक तत्वों का खजाना है, इसका सेवन रोगों से लड़ने की क्षमता और वजन नियंत्रण में सहायक है। कैंसर से बचाव और दिल की सेहत को ठीक रखने में इसके लाभ देखे गए हैं।

कैंसर का कम होता है खतरा

ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफेन एक शक्तिशाली यौगिक है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद कर सकता है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार, सल्फोराफेन शरीर में मौजूद कैंसरकारक एंजाइम को निष्क्रिय करता है और डीएनए को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ब्रोकली को विशेष रूप से फेफड़े, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर के खतरे को कम करने में प्रभावी पाया गया है।

हार्ट के लिए भी लाभकारी

ब्रोकली हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसमें मौजूद पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अमेरिका की नेशनल हार्ट, लंग्स एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के अनुसार, उच्च फाइबर युक्त आहार जैसे ब्रोकली हृदय रोग का जोखिम 20–25% तक कम कर सकता है। ब्रोकली में सल्फोराफेन और फ्लावोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व धमनियों में सूजन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों में प्लाक जमना) का खतरा घटता है।

ब्रोकली के साइड-इफेक्ट्स भी जानिए

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, ब्रोकली में भरपूर पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसके सेवन को लेकर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। ब्रोकली में मौजूद फाइबर और रैफिनोज पाचन की समस्या पैदा कर सकते हैं।

पोषण विशेषज्ञ, वजन प्रबंधन और हृदय स्वास्थ्य विशेषज्ञ ब्रोकली ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होती है, लेकिन यह पाचन संबंधी -समस्याओं को जन्म दे सकती है। थायरॉइड के कार्य में बाधा डाल सकती है और कुछ परिस्थितियों में दवाओं के अवशोषण को भी प्रभावित कर सकती है।

क्या कहती हैं आहार विशेषज्ञ?

आहार विशेषज्ञ पायल शर्मा कहती हैं, अधिक मात्रा में सेवन के कारण ब्रोकली में मौजूद फाइबर गैस और सूजन का कारण बन सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा किडनी की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए।

ब्रोकली एक हाई फाइबर वाली सब्जी है, जिसमें रैफिनोज होता है। यह मानव आंत में ठीक से पचती नहीं है, जिसके कारण गैस बनने, पेट फूलने और ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है। थाइरॉइड और कमजोर पाचन वाले भी इसका अधिक सेवन करने से बचें।

चेहरे को चमका सकता है कच्चा दूध, बस इस्तेमाल का सही तरीका जान लें

चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए बाजार में तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं। इनके इस्तेमाल से चेहरे को इंस्टेंट ग्लो मिलता है। पर, कई बार ये प्रोडक्ट त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आज के समय में अभिनेत्रियों से लेकर आम लोग भी घरेलू नुस्खे आजमाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी के चलते हम आज आपको बताएंगे कच्चे दूध का फायदा।

दरअसल, बाजार में मिलने वाला कच्चा दूध स्किन को काफी लाभ पहुंचाता है। इसका लाभ तब सबसे ज्यादा मिलता है, जब आप इसका इस्तेमाल सही तरह से करेंगी। इसी के चलते आज इस लेख में हम आपको स्किन पर कच्चे दूध के इस्तेमाल का तरीका बताने जा रहे हैं।, ताकि घर बैठे आप पाएं दमकती और निखरती त्वचा.....

चेहरा दमकाने का सामान

2-3 बड़े चम्मच कच्चा दूध
1 चम्मच बेसन

पैक बनाने का तरीका

इसका पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में कच्चा दूध लें। अब इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करके पेस्ट तैयार करें। ध्यान रखें कि ये पेस्ट एकदम से पतला न हो जाए। अगर पेस्ट पतला हो गया तो इसे चेहरे पर अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएं और थोड़ी देर उसे ऐसे ही रहने दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं।

इस्तेमाल का तरीका

अब बारी आती है इस पैक को इस्तेमाल करने की तो उसके लिए सबसे पहले अपना चेहरा और गर्दन अच्छी तरह से धो लें। इसके लिए किसी अच्छे फेसवॉश का इस्तेमाल करें। फेसवॉश इस्तेमाल करवे के बाद आपका चेहरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा।

अब एक ब्रश की मदद से मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं। अब 15-20 मिनट तक सूखने दें। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। चेहरा धोने के बाद हल्के हाथों से चेहरे को थपथपाते हुए पोंछ लें। इसके बाद मॉइश्चराइज और टोनर का इस्तेमाल अवश्य करें। इससे आपका चेहरा खिल उठेगा।

कब कर सकते हैं इस्तेमाल

यदि आप इस पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो याद रखें कि इसे सिर्फ सप्ताह में 2-3 बार इस पैक का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये चेहरे को डैमेंज कर सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तीन बार इसका इस्तेमाल करें।

बरतें ये सावधानी

इस पैक को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दरअसल, ये हर किसी को सूट नहीं करता है। इसलिए यदि पहली बार इस पैक का इस्तेमाल करना है तो पहले पैच टेस्ट करें, ताकी किसी तरह की एलर्जी का खतरा न रहे।

अपनाएं ये रूटीन तो बारिश के मौसम में भी नहीं झड़ेंगे बाल!

बरसात के मौसम में बाल देर से सूखते हैं और अक्सर चिपचिपे, बेजान और रूखे नजर आने लगते हैं। ऐसे में आप अपने बालों की देखभाल कैसे करती हैं?

मानसून में ठंडी बूंदों की फुहारें तपती गर्मी से राहत देकर मन को खुश कर जाती हैं। वहीं बालों की देखभाल मानसून में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी अधिक होती है, जिससे बाल चिपचिपे और कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। ऐसे में मानसून में आपको अपने बालों की विशेष देखभाल करनी होगी।

साफ पानी से धोएं

बारिश का पानी आपको प्राकृतिक और शुद्ध लग सकता है, लेकिन शहरों में यह पानी धूल, गंदगी और प्रदूषित पदार्थों से भरा होता है। जब बाल बारिश के पानी में भीगते हैं तो यह उनकी जड़ों को कमजोर करता है और रूसी, खुजली जैसी समस्याएं बढ़ा देता है। साथ ही जब बरसात में गीले बालों पर ठंडी हवा लगती है तो उनके टूटने और झड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए बारिश में भीगने के बाद बालों को साफ पानी से धोकर जल्दी सूखा लें।

हल्के तेल की मालिश

इस मौसम में बहुत गाढ़े या हैवी तेलों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे बाल चिपचिपे और कमजोर हो सकते हैं। नारियल, बादाम, जैतून या आर्गन जैसे हल्के तेलों से सप्ताह में 1-2 बार हल्का मसाज करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तेल लगाने के बाद एक घंटे तक छोड़ना बेहतर है। रात भर तेल लगाकर सोने से धूल और गंदगी चिपक सकती है, जिससे स्कैल्प में खुजली या संक्रमण हो सकता है।

सल्फेट मुक्त शैंपू

मौसम कोई भी हो, बालों की देखभाल के लिए सौम्य और सल्फेट मुक्त शैंपू का उपयोग जरूरी है, क्योंकि सल्फेट युक्त शैंपू बालों के प्राकृतिक तेल छीन लेता है, जिससे बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं। सल्फेट मुक्त शैंपू स्कैल्प को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई करता है। वहीं मानसून में शैंपू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें। यह बालों की नमी बनाए रखता है।

तौलिया और कंघी

मानसून में बाल भीगना सामान्य है, लेकिन गीले बालों में कंघी करने से वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। आप हमेशा साफ कंघी का ही उपयोग करें और उसे नियमित रूप से धोएं। बाल सुखाने के लिए तौलिए से जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से पोंछें। तौलिया या कंघी किसी के साथ शेयर न करें, ताकि फंगल संक्रमण से बचा जा सके।

कूल मोड पर ड्रायर

स्टाइलिश दिखना जरूरी है, लेकिन बरसात के मौसम में आपको स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर, हेयर कलर और केमिकल ट्रीटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ये बालों को कमजोर और बेजान बना देते हैं। ये उपकरण बालों की प्राकृतिक नमी छीन लेते हैं और बाल रूखे हो जाते हैं। हालांकि अगर ड्रायर का उपयोग जरूरी हो तो 'कूल मोड' पर ही इस्तेमाल करें।

हेयर स्टाइल

खुले बाल आपको पंसद हैं और हर आउटफिट पर अच्छे लगते हैं, लेकिन इस मौसम आपको बाल खूले रखने से बचना चाहिए। आपको एक ऐसा हेयर स्टाइल चुनना चाहिए, जो बालों को सुरक्षित रखे। आप खुले बालों के बजाय चोटी, जूड़ा या बन बना सकती हैं। ये बालों को उलझने और टूटने से बचाते हैं।

सप्ताह में 1 से 2 बार हेयर मास्क लगाएं

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के सीनियर रेजिडेंट, त्वचा विज्ञान विभाग डॉ. अमित कुमार मीणा का मानना है कि बरसात के मौसम में आपके बालों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले तो आप गीले बालों में बाहर न निकलें। जल्दी है तो बालों को पहले मुलायम तौलिए से हल्के हाथों से पोंछें, फिर हेयर ड्रायर को कम तापमान या 'कूल मोड' पर रखकर बालों को सुखाएं। हीट स्टाइलिंग टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल न करें। बालों की जड़ों को पोषण देने के लिए हाइड्रेशन बनाए रखें, खूब पानी पीएं और संतुलित आहार लें। सप्ताह में 1-2 बार हेयर मास्क या डीप कंडीशनिंग करें। शैंपू के दौरान स्कैल्प की हल्की मालिश करें और टाइट हेयर स्टाइल से बचें। ढीली चोटी या प्राकृतिक स्टाइल को प्राथमिकता दें।

'किसानों के हित से कोई समझौता नहीं, भारत-यूएस ट्रेड डील पर सरकार का बड़ा बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, वह अन्य पड़ोसी देशों के साथ यूएस द्वारा की गई ट्रेड डील के मुकाबले काफी अच्छी है। इसमें देश के किसानों, डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए, भारत के लिए एक बहुत अच्छी डील पक्की करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल किया है। यह ट्रेड डील अर्थव्यवस्था के अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर, सीफूड और रत्न और आभूषण को फायदा पहुंचाएगी और इससे अमेरिका को निर्यात के लिए बड़े अवसर खुलेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स और अन्य सामान शामिल हैं, उन्हें भी इस डील से फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एमएसएमई सेक्टर, जो इकॉनमी में सबसे अधिक नौकरियां पैदा करता है, उसे भी इस ट्रेड डील से फायदा होगा क्योंकि कम टैरिफ से इस सेक्टर से होने वाला निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। गोयल ने बताया कि पीएम मोदी ने यह डील फाइनल की है, जो अधिकारियों और मंत्रियों के लेवल पर लंबी बातचीत में फंसी हुई थी और जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था।

उन्होंने तर्क दिया कि व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना आवश्यक था क्योंकि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के उच्च शुल्क के कारण अमेरिका को खाद्य पदार्थ और वस्त्र जैसे श्रम-प्रधान उत्पादों के भारतीय निर्यात पर गहरा असर पड़ा था। उन्होंने कहा, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से, मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह समझौता भारत के आर्थिक विकास, किसानों, गरीबों, मछुआरों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई अवसर लेकर आएगा।

गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन पर देश को गुमराह करने और भारत के विकास के प्रति चिंता न दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच वाले नेता देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें देश की प्रगति की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस सरकार ने भारत को दुनिया की पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में धकेल दिया था और अगर राहुल गांधी की मनमानी चली तो वे देश को फिर से उसी स्थिति में ले जाएंगे।

इस एआई टूल से अमेरिका से लेकर भारत तक कोहराम, आईटी शेयर हुए धड़ाम

मुंबई, एजेंसी। भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार सुबह मामूली बढ़त देखी गई, जिसमें सभी सेक्टरों में बढ़त हुई। लेकिन, आईटी शेयरों में गिरावट से यह बढ़त सीमित रही। एंथ्रोपिक द्वारा अपने क्लाउड एआई चैटबॉट के लिए एक लीगल टूल लॉन्च करने के बाद, एआई में बढ़ते कॉम्पिटिशन और कम मार्जिन की वजह से नेगेटिव वॉल स्ट्रीट संकेतों को ट्रैक करते हुए भारतीय आईटी शेयरों में गिरावट आई।

सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 44 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 83,783 पर पहुंच गया, और निफ्टी 51 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 25,778 पर बंद हुआ। मुख्य ब्रॉड-कैप इंडेक्स में मामूली बढ़त देखी गई, क्योंकि निफ्टी मिडकैप 100 में 0.04 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.01 प्रतिशत की बढ़त हुई।

आईटी और रियल्टी को छोड़कर सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में थे, जो क्रमशः 5.39 प्रतिशत और 0.58 प्रतिशत नीचे थे। निफ्टी ऑटो, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस प्रमुख गेनर थे, जो क्रमशः 1.12 प्रतिशत, 1.38 प्रतिशत, 1.05 प्रतिशत और 1.77 प्रतिशत ऊपर थे। मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि निफ्टी के लिए तुरंत सपोर्ट 25,550-25,600 जोन पर है, जबकि रेजिस्टेंस 25,850–25,900 जोन पर है।

एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया है कि यूएस-इंडिया ट्रेड डील से शुरू हुई रैली को बनाए रखने में रुकावटें आएंगी, और मंगलवार को यूएस में आईटी शेयरों में बिकवाली से भारतीय आईटी इंडेक्स नीचे जा सकता है। भारत कई अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है। नए एंथ्रोपिक एआई लॉन्च के बाद वॉल स्ट्रीट पर सॉफ्टवेयर शेयरों में 25 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि ज्यादातर सेक्टर्स में, वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा हैं, इस कारण लगातार तेजी के लिए कोई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है। 6 फरवरी को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेट्स में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है।

गुरुवार को देखी गई तेजी मुख्य रूप से एफआईआई शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी। टेक्सटाइल और कपड़ों, रत्न और आभूषण और मरीन प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स, जिन्हें अमेरिका को एक्सपोर्ट से फायदा होने की उम्मीद है, उनमें कुछ और प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा।

एशियाई बाजारों में, चीन का शंघाई इंडेक्स फ्लैट रहा और शेनझेन में 0.88 प्रतिशत की गिरावट आई, जापान का निक्केई 0.6 प्रतिशत गिरा, और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.73 प्रतिशत नीचे आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.72 प्रतिशत बढ़ा।

पिछले ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार ज्यादातर हरे निशान में बंद हुए, जबकि नैस्डैक में 1.43 प्रतिशत की गिरावट आई। एसएंडपी 500 में 0.84 प्रतिशत की गिरावट आई, और डॉव जोन्स 0.34 प्रतिशत नीचे आया। 3 फरवरी को, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,236 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,014 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे।

क्या जनरल टिकट पर मिलता है रेलवे का बीमा? अच्छे-अच्छों को नहीं पता होगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी एक बहुत बड़ी आबादी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन के सफर पर निर्भर करती है। टिकट बुक करने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक की प्रक्रिया से तो लगभग हर यात्री वाकिफ है, लेकिन रेलवे से जुड़ी कुछ ऐसी तकनीकी जानकारियां भी हैं, जिनसे अधिकतर लोग अनजान रहते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को बीमा (इंश्योरेंस) की सुविधा मिलती है? यह जानकारी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहद मायने रखती है जो अक्सर जनरल डिब्बों में यात्रा करते हैं।

जनरल टिकट और बीमे का सच

अगर आप भी उन लाखों यात्रियों में शामिल हैं जो जनरल टिकट लेकर सफर करते हैं, तो आपको रेलवे के इस नियम के बारे में पता होना चाहिए। रेलवे के नियमों के मुताबिक, जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले मुसाफिरों को यात्रा बीमा की सुविधा नहीं दी जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि टिकट खरीदते ही वे बीमित हो गए हैं, लेकिन जनरल क्लास के मामले में ऐसा नहीं है।

हालांकि, यहां राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की दुर्घटना या हादसा होने की स्थिति में रेलवे अधिनियम 1989 के तहत पीड़ित यात्रियों को मुआवजा जरूर दिया जाता है, लेकिन यह ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी से अलग प्रक्रिया है।

सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलता है फायदा

अब सवाल उठता है कि आखिर यह इंश्योरेंस किसे मिलता है? रेलवे की तरफ से दी जाने वाली इंश्योरेंस स्कीम केवल उन यात्रियों के लिए है जो आरक्षित श्रेणियों (स्लीपर, 1एष्ट, 2एष्ट, 3एष्ट) में सफर करते हैं। इसमें भी एक बड़ी शर्त लागू होती है। यह सुविधा केवल उन यात्रियों को मिलती है जिन्होंने अपना टिकट इ्रक्रष्टञ्जष्ट की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुक किया हो। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से लाइन में लगकर कंफर्म टिकट भी लिया है, तो भी आप इस इंश्योरेंस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। साथ ही, यह स्कीम पैसेंजर ट्रेनों और सब-अर्बन ट्रेनों के यात्रियों पर लागू नहीं होती है।

जमात-ए-इस्लामी के बदले तेवर, चुनावी घोषणापत्र में भारत से अच्छे रिश्तों का वादा

ढाका, एजेंसी। महीने 12 फरवरी को चुनाव हैं। ऐसे में देश के अंदर प्रमुख राजनीतिक दल जमात-ए इस्लामी एक अहम ताकत के रूप में उभरती नजर आ रही है। भारत विरोधी गुट के रूप में पहचान जाने वाले जमात ने अपना बुधवार (04 फरवरी) को घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया।

बांग्लादेश की प्रमुख इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने चुनावों से पहले 41 सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया, जिसमें न्याय और आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के साथ-साथ मंत्रिमंडल में महिलाओं को शामिल करने का वादा किया गया है। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पार्टी के सत्ता में आने पर 'राजकब्जा में पर्याप्त संख्या में महिलाओं को शामिल करने' का वादा किया गया।, हालांकि पार्टी ने कोई भी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतार है।

पड़ोसी देशों के साथ बेहतरी संबंध पर जोर

इस्लामिक कंजर्वेटिव पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने अपने घोषणापत्र में भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक और सहयोगात्मक रिश्ते बनाए रखने का वादा किया है। पार्टी के बयान के अनुसार ये संबंध आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधारित होंगे। घोषणापत्र में दावा किया गया कि भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और थाइलैंड के साथ शांतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित किए जाएंगे। पार्टी ने जोर दिया कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए पड़ोसियों के साथ संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

अमेरिकी कानून का सामना कर रहे मादुरो की बढ़ी मुश्किलें, यूएस से अर्जेंटीना ने की प्रत्यर्पण की मांग

अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के एक जज ने बुधवार को अमेरिका से वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सौंपने की औपचारिक मांग की है। फिलहाल वह न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद हैं और उन पर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना ने एक विशेष ऑपरेशन में पिछले महीने मादुरो को पकड़ा था।

मादुरो पर लगे हैं कई गंभीर आरोप

मामले में अर्जेंटीना के संघीय जज ने एक वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस काराकास में मादुरो पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने शासन के दौरान प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा करवाई। इसमें लोगों को प्रताड़ित करना और जबरन गायब करना शामिल है।

मामलों में नागरिकों को बनाया गया है वादी

इस मामलों में उन वेनेजुएला के नागरिकों को वादी बनाया गया है जिन्होंने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंटों के हाथों भयानक यातनाएं झेली हैं। यह कानूनी लड़ाई साल 2023 में ब्यूनस आयर्स में मानवाधिकार संगठनों ने शुरू की थी। यहां की अदालतें पहले भी देश के बाहर मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करती रही हैं। तीन जनवरी को अमेरिकी सेना ने मादुरो को सत्ता से हटाया था, जिसके बाद अर्जेंटीना के सरकारी वकीलों ने जज रामोस से इस प्रत्यर्पण अनुरोध को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।

अमेरिका में इस मामले में चल रहा केस

अर्जेंटीना ने 1997 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए यह मांग की है। हालांकि, इसकी संभावना कम है कि ट्रंप प्रशासन इस पर तुरंत अमल करेगा। इसका मुख्य कारण अमेरिका में मादुरो पर चल रहा मुकदमा है। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स अभी ब्रुकलिन की जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 वर्षों तक ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में हजारों टन ड्रग भेजने में मदद की।

क्या है राजनीतिक समीकरण?

राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली खुद को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी सहयोगी मानते हैं और उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी का स्वागत किया था। मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रत्यर्पण अनुरोध को ऐतिहासिक बताया है। 'अर्जेंटीना फोरम फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी' ने कहा कि यह उन पीड़ितों की जीत है जिन्होंने ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। अब अर्जेंटीना का विदेश मंत्रालय यह आधिकारिक अनुरोध वाशिंगटन डीसी भेजेगा, जहां अमेरिकी कानूनी विभाग इस पर विचार करेगा।

'कभी हंसते नहीं देखा, सबसे खराब रिपोर्टर', एपस्टीन फाइल्स पर पूछा सवाल तो महिला पत्रकार पर भड़के ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों और तेवर के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभाल रहे ट्रंप के कई कदमों में पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हाल ही में ट्रंप एपस्टीन फाइल्स, वेनेजुएला सहित कई मामलों पर अमेरिकी मीडिया के निशाने पर हैं। इस बीच ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता के दौरान महिला पत्रकार पर व्यक्तिगत निशाना साधा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ओवल ऑफिस में महिला पत्रकार पर निजी टिप्पणी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (03 फरवरी) को ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान एपस्टीन फाइलों के बारे में सवाल पूछे जाने पर ट्रंप भड़के हुए नजर आए। ऐसे में उन्होंने सीएनएन की महिला संवाददाता की आलोचना की। ट्रंप ने उन्हें 'सबसे खराब पत्रकार' कहा और उनके संस्थान को 'बेईमान संगठन' बताया।

कॉलिन्स ने दावा सवाल, भड़के ट्रंप क्या बोले?

दरअसल, सीएनएन की वरिष्ठ व्हाइट हाउस संवाददाता कैटलान कॉलिन्स ने डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी अहम जानकारी को संपादित करने और एपस्टीन पीड़ितों की नाराजगी के बारे में सवाल दागा, उन्होंने सीधा राष्ट्रपति से पूछा कि पीड़ित लोगों से आप क्या कहेंगे, जिनका न्याय नहीं मिला है। इस सवाल पर थोड़े असहज दिखे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, 'मुझे लगता है कि अब देश को किसी और चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है।' इसी के साथ उन्होंने महिला पत्रकार को सबसे खराब बताया और कहा कि मैंने कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। इसी के साथ उनके मीडिया संस्थान को भी घेरा। जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब ट्रंप और कॉलिन्स के बीच बहस देखी गई है।

अब जानिए वीडियो में क्या है?

महिला पत्रकार ने सवाल पूछा कि डीओजी की ओर से एपस्टीन फाइल्स में संपादन की वजह से पीड़ितों में नाराजगी है। उन्होंने ट्रंप से पूछा कि न्याय न मिलने से पीड़ितों से आप क्या कहेंगे? इस सवाल के बाद पहले को ट्रंप थोड़ा शांत नजर आए फिर जवाब देते हुए कहा कि मेरे बारे में कुछ नहीं निकला, ये मेरे खिलाफ साजिश थी। उन्होंने आगे कहा कि देश को अब स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। करना चाहिए। हालांकि जब पत्रकार कॉलिन्स ने पीड़ितों के बयान पर जोर दिया तो ट्रंप भड़क हुए नजर आए और दो टूक कहा कि 'आप सबसे खराब रिपोर्टर हैं'। इतना ही नहीं यह भी कहा कि आप जैसे लोगों की वजह से सीएनएन की रेटिंग्स गिर रही हैं।

ट्रंप ने आगे उखड़ते हुए कहा कि आप एक युवा महिला हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपको मुस्कुराते देखा है। मैं आपको 10 साल से जानता हूं, आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी। आप इसलिए नहीं मुस्कुरा रही, क्योंकि आप जानती हैं कि सच नहीं बोल रही।

इजराइल के सैनिक ही कर रहे थे हमास की मदद? गाजा में सिगरेट-मोबाइल तस्करी के गंभीर आरोप

यरुशलम, एजेंसी। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने गाजा में अवैध तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सरकारी अभियोजकों के मुताबिक इस मामले में करीब एक दर्जन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें इजराइली सैनिक और रिजर्व फोर्स के सदस्य भी शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने युद्ध के दौरान गाजा में लाखों डॉलर के सामान की तस्करी कर न सिर्फ कानून तोड़ा, बल्कि दुश्मन संगठन हमास की मदद भी की।

इजराइल के अभियोजक द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि आरोपियों ने सिगरेट, आईफोन, बैटरियां, कम्युनिकेशन केबल और कार के पुर्जे जैसे सामान गाजा में अवैध रूप से पहुंचाए। आरोप यह भी है कि तस्करी के वक्त उन्हें यह पूरी जानकारी थी कि यह सामान हमास और उसके लड़ाकों तक पहुंच सकता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह तस्करी इज़राइल-गाजा सीमा पर कमजोर निगरानी की वजह से संभव हो पाई। इज़राइली अखबार हाआरेत्ज़ ने दावा किया कि सक्रिय ड्यूटी और रिज़र्व सैनिकों की मिलीभगत से यह धंधा चल रहा था। गौरतलब है कि युद्ध के दौरान गाजा में मानवीय सहायता तक को सख्त नियंत्रण में रखा गया है और कई सामानों को हमास के लिए फायदेमंद बताकर प्रतिबंधित किया गया है।

सीलबंद ट्रकों का खेल

एसोसिएटेड प्रेस को मिली गाजा चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक आंतरिक प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि सीलबंद इजराइली ट्रकों के जरिए महंगे सामान गाजा पहुंचाए जा रहे थे। ये ट्रक आधिकारिक क्रॉसिंग सिस्टम के बाहर, इजराइल के अज्ञात संपर्कों के जरिए समन्वय करके भेजे जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक, हर शिपमेंट पर अवैध शुल्क लाखों डॉलर तक पहुंच सकता था।

शिन बेट प्रमुख के भाई का नाम

इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब अभियोजक के बयान में शिन बेट (इज़राइल की घरेलू खुफिया एजेंसी) के प्रमुख डेविड जिनी के भाई, बेजालेल जिनी का नाम सामने आया। आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर सिगरेट की तस्करी में मदद की। हालांकि, बेजालेल जिनी पर फिलहाल औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं और उनके वकील ने सभी आरोपों से इनकार किया है। अभियोजक कार्यालय ने आरोपियों की संपत्ति जिसमें गाड़ियां, अचल संपत्ति और नकदी शामिल है जब्त करने की मांग की है। यह मामला इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था, सेना की जवाबदेही और युद्धकालीन भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

जिस दिन हादसा हुआ, उस दिन मुझे भी अजित पवार के साथ यात्रा करनी थी : महादेव जानकर

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने दावा किया है कि पिछले सप्ताह बारामती में हुए विमान हादसे वाले दिन उन्हें भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ यात्रा करनी थी, लेकिन मुंबई देर से पहुंचने के कारण वह उनके साथ नहीं जा सके। पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर 28 जनवरी को सुबह करीब आठ बजकर 45 मिनट पर एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें मुंबई से सवार अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) के प्रमुख जानकर ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दुर्घटना से कुछ दिन पहले उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता पवार से बातचीत हुई थी और उन्हें उसी विमान से बारामती जाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा, "हालांकि मैं मुंबई देर से पहुंचा, जिसके कारण मैं अजित पवार के साथ बारामती विमान से नहीं जा सका। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और पवार की मृत्यु राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है।" धनगर (चरवाहा) समुदाय के नेता जानकर पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में प्रभाव रखने वाली आरएसपी के प्रमुख हैं। वह 2016 में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार में पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन मंत्री रहे थे।

'हिंसा और धमकियों के सिस्टमैटिक पैटर्न को रोकिए...', SC में SIR को लेकर बोला चुनाव आयोग

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग की है। आयोग ने कोर्ट से कहा है कि SIR का काम कर रहे अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों के एक सिस्टमैटिक पैटर्न को रोका जा सके।

आयोग ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के भाषणों से ऐसी स्थितियों को बढ़ावा मिला, जबकि पुलिस दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। EC ने अपने हलफनामे में कहा, 'यह साफ तौर पर दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाली चुनौतियां SIR प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये राज्य मशीनरी की कमियों और वहां मौजूद राजनीतिक दखल के माहौल का सीधा नतीजा हैं।' हलफनामे में कहा गया, 'यह विचित्र और चिंताजनक गड़बड़ी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए SC के तुरंत दखल की मांग करती है। CM ने लगातार कई ऐसे सार्वजनिक भाषण दिए हैं जो स्वाभाविक रूप से भड़काऊ हैं, जिससे चुनाव अधिकारियों के बीच डर का माहौल बन रहा है'।

'उत्तर भारत के लोग टेबल साफ करने आते हैं...', तमिलनाडु के मंत्री का विवादित बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर के लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलतीं और वे तमिलनाडु आकर टेबल साफ करने, मजदूरी करने या पानी पूरी बेचने जैसे काम करते हैं।

वहीं, तमिलनाडु की दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) की वजह से यहां के बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगहों पर करोड़ों कमा रहे हैं। यह बयान दो-भाषा बनाम तीन-भाषा की पुरानी बहस को फिर से भड़का रहा है, खासकर जब विधानसभा चुनाव बस कुछ हफ्तों दूर हैं। मंत्री ने चेंगलपट्टू जिले में एक पार्टी कार्यक्रम में यह बात कही है। उन्होंने कहा, 'उत्तर के लोग यहां टेबल साफ करने आते हैं... वे कंस्ट्रक्शन मजदूर बनकर या पानी

पूड़ी बेचकर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी सीखी है।' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन हमारे बच्चे दो-भाषा नीति की वजह से अंग्रेजी अच्छी तरह सीखते हैं और विदेश जाते हैं। वे अमेरिका, लंदन में करोड़ों कमाते हैं।'

भाजपा ने की कड़ी निंदा

बीजेपी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि डीएमके नेता बार-बार प्रवासी मजदूरों, खासकर उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषियों को निशाना बना रहे हैं।

तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने एक्स पर पोस्ट किया कि मंत्री ने उत्तर भारतीयों को 'टेबल क्लीनर और पानी पूरी सेलर' कहकर मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा, 'आज के भारत में हर राज्य के लोग हर जगह काम करते हैं। कोई काम छोटा नहीं, कोई नागरिक हीन नहीं।' बीजेपी ने डीएमके पर सामाजिक विभाजन फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह पार्टी उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है।

धुरंधर : द रिवेंज टीजर रिलीज, ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, रणवीर सिंह का दिखा रहमान डकैत अंदाज

रणवीर सिंह और आदित्य धर की एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी की पहली हिट फिल्म धुरंधर की कामयाबी के बाद फिल्म के दूसरे पार्ट धुरंधरः द रिवेंज का सभी को बेसब्री से इंतजार है। धुरंधरः द रिवेंज का टीजर रिलीज हो गया है। धुरंधरः द रिवेंज के टीजर ने बता दिया है कि धुरंधर की तरह धुरंधरः द रिवेंज भी बॉक्स ऑफिस बवाल मचाने वाली है। बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था। अब धुरंधरः द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी इसका इंतजार रहेगा। इससे पहले देखते हैं धुरंधरः द रिवेंज का दमदार टीजर।

धुरंधरः द रिवेंज के टीजर ने दर्शकों के हिलाकर रखने का काम किया है। धुरंधरः द रिवेंज के टीजर ने बताया है कि बॉक्स ऑफिस पर उसके सामने कोई भी फिल्म आ जाए, वह अपनी जीत सुनिश्चित करके रहेगी। धुरंधरः द रिवेंज का टीजर 1।12 मिनट का है, जिसमें रणवीर सिंह मारकाट और गोलीबारी करते दिख रहे हैं। इसमें रणवीर सिंह दो किरदारों में एक मिशन पूरा करते दिख रहे हैं। टीजर में रहमान डकैत भी दिख रहा है। वहीं, इस टीजर को शेयर कर मेकर्स ने लिखा है, यह नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।

धुरंधरः द रिवेंज की रिलीज का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है। फिल्म अगले महीने मार्च की 19 तारीख को रिलीज हो रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन एक बार फिर नजर आएंगे। वहीं, पार्ट 1 में मर चुके रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) का फ्लैश बैक नजर आने वाला है। दर्शक अब पाकिस्तान के लयारी में हमजा अली (रणवीर सिंह) का दबदबा देखने जा रहे हैं।

बता दें, 19 मार्च 2026 को इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। दोनों ही फिल्म के मेकर्स ने पीछे ना हटने की कसम खा ली है। लेकिन इससे दोनों ही फिल्मों की कमाई पर बहुत बुरा असर जरूर पड़ने वाला है। क्योंकि धुरंधर की ऑडियंस तैयार बैठी है और इधर यश पूरे चार साल बाद कोई फिल्म ला रहे हैं। ऐसे में दोनों ही फिल्मों दर्शकों के लिए जरूरी हो गयी हैं।

मैं फेल हो सकती हूं, मगर हार नहीं मानूंगी : पायल राजपूत

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की उभरती एक्ट्रेस पायल राजपूत ने अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानी के साथ अपने मजबूत इरादे को जाहिर किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह कभी हार नहीं मानेंगी। पायल ने स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें एक्टिंग छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे दृढ़ हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, वे चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं, और मैं खुद से सवाल करती हूं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर मैं पिछले 12 सालों में की गई कड़ी मेहनत के बारे में सोचती हूं। इसलिए मैं खुद से कहती हूं नहीं, मैं फेल हो सकती हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगी। नेपोटिज्म जैसे गंभीर मुद्दों पर पायल अक्सर अपने राय रखती रहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद और फेवरेटिज्म पर खुलकर बात की थी। उन्होंने लिखा था कि एक्टर बनना सबसे मुश्किल करियर में से एक है। हर दिन अनिश्चितता के साथ शुरू होता है, जहां टैलेंट से ज्यादा विशेषाधिकार और कनेक्शन हावी हो जाते हैं।

पायल ने बताया था कि कई बार उन्हें शक होता है कि उनकी मेहनत और लगन ऐसी दुनिया में नोटिस होगी भी या नहीं। मौके अक्सर मशहूर सरनेम या पावरफुल एजेंट वाले लोगों के पास चले जाते हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और टैलेंट पर भरोसा रखा।

फिलहाल पायल कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। वह तेलुगू फिल्म वेंकटलक्ष्मी में नजर आने वाली हैं, जिसे मशहूर डायरेक्टर मुनि बना रहे हैं। मेकर्स इस फिल्म को तेलुगू, तमिल और हिंदी में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, पायल के पास एक और तमिल फिल्म है। अनटाइटल्ड फिल्म एक बड़े बजट का प्रोजेक्ट है, जिसे जाने-माने डायरेक्टर आर.एस. दुरई सेंथिलकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं।

शूटिंग का पहला फेज चेन्नई में पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक रोमांचक एक्शन-ड्रामा है। संगीत जिब्रान दे रहे हैं, सिनेमैटोग्राफी एस. वेंकटेश की है, एडिटिंग प्रदीप कर रहे हैं और आर्ट डायरेक्शन दुरईराज संभाल रहे हैं।

अभिनेत्री ईशा रेब्बा का आरोप ; इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कमेंट्स के जरिए किया गया परेशान ; दर्ज की शिकायत

तेलुगु इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री ईशा रेब्बा ने आज बुधवार को हैदराबाद में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि एक अनजान व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार-बार आपत्तिजनक कमेंट्स करके उन्हें टारगेट कर रहा है। शख्स उनकी छवि खराब कर रहा है। उन्होंने संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट्स की डिटेल्स और आपत्तिजनक कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भी जमा किए हैं।

ईशा रेब्बा ने क्या आरोप लगाया है?

ईशा ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के प्रमोशनल एक्टिविटीज के दौरान ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के एक गंभीर मामले पर ध्यान दिलाने के लिए एक लेटर जमा किया है। उनका आरोप है कि प्रमोशन के दौरान, एक सोशल मीडिया अकाउंट से शख्स ने एक पब्लिक सोशल मीडिया पेज पर आपत्तिजनक और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की। कमेंट में इस्तेमाल की गई भाषा बहुत परेशान करने वाली, अपमानजनक है और मानसिक उत्पीड़न के बराबर है।

जांच में जुटी पुलिस

बंजारा पुलिस के मुताबिक, 'शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसा कंटेंट न सिर्फ एक महिला के तौर पर उनकी गरिमा को टारगेट करता है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी परेशान करता है। यह सार्वजनिक अपमान करने वाली टिप्पणी है। इस घटना से उन्हें मानसिक रुप से काफी परेशानी हुई है'। ईशा ने पुलिस स्टेशन में इंस्टाग्राम पर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

तेलुगु इंडस्ट्री में एक्टिव हैं ईशा रेब्बा

आपको बता दें कि ईशा रेब्बा एक चर्चित भारतीय अभिनेत्री हैं। वे मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें अंथाका मुंदू आ तरवाथा, बंदिपोटू, ओयी, अमी थुमी, दर्शाकुडू और अवे में अहम भूमिकाएं अदा कर दर्शकों के बीच पहचान बनाई है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com